



कुवैत में भारतीय कामगारों से मिले पीएम मोदी, बोले- गरीबों की गरिमा और सम्मान मेरे लिए सबसे अहम



नई दिल्ली। कुवैत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गल्फ स्पिक लेबर कैंप का दौरा किया, जहां उन्होंने भारतीय कामगारों से मुलाकात की। ऋतु मोदी ने बातचीत के दौरान कहा, जब मैं साल 2047 के विकसित भारत की बात करता हूँ, तो मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे भारतीय भाई, जो अपने घरों से दूर यहां काम कर रहे हैं, भी ये सपना देखते हैं कि उनके गांव में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बने। उनकी महत्वाकांक्षा ही भारत की ताकत है। उन्होंने कहा, मेरे देश के किसान और मजदूर बहुत मेहनत करते हैं। अगर वे 10 घंटे काम कर सकते हैं, तो मुझे 11 घंटे काम करना चाहिए। अगर वे 11 घंटे काम करते हैं, तो मुझे 12 घंटे काम करना चाहिए। आप अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, और मैं अपने 140 करोड़ देशवासियों के परिवार के लिए मेहनत करता हूँ। प्रधानमंत्री ने विकास की परिभाषा को समझाते हुए कहा कि सड़कें, हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन तो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन गरीबों के घर में शौचालय बनाना भी विकास है। उन्होंने कहा, हमने देश में 11 करोड़ शौचालय बनाने का फैसला किया। अब तक 4 करोड़ पक्के मकान बनाए गए हैं, जिनमें करीब 15-16 करोड़ लोग रह रहे हैं। इसके अलावा, नल से जल पहुंचाने की कोशिश जारी है। मेरे लिए गरीबों की गरिमा और सम्मान ही सबसे अहम है। मोदी ने बताया कि भारत में सबसे सस्ता इंटरनेट उपलब्ध है, जिससे प्रवासी भारतीय अपने परिवारों से आसानी से जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, अब कोई भी कम लागत पर

वीडियो कॉल के जरिए अपने परिवार से बात कर सकता है। इससे दूरी कम हुई है और परिवार करीब आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने भारतीय कामगारों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और महत्वाकांक्षा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए शनिवार को यहां कहा कि भारत में "विश्व की कौशल राजधानी (स्किल कैपिटल) बनने का सामर्थ्य है। मोदी शहर के शेख साद अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित विशेष कार्यक्रम 'हला

विस्फोट के बाद 600 किलोमीटर तक मदद के लिए भागा झुलसा व्यक्ति, मदद करने की जगह लोग बनाते रहे वीडियो



जयपुर-अजमेर नेशनल हाईवे पर शुक्रवार को गैस टैंकर में जबरदस्त विस्फोट देखने को मिला है। इस विस्फोट के बाद लोग मदद मांगने के लिए इधर उधर दौड़ते भागते रहे ताकि अपनी जान बचा सकें। इसी बीच ऐसा मामला पता चला है कि कुलुयुग में इंसानियत बिलकुल खत्म हो चुकी है। आज के समय में लोगों के लिए सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए कटेड बनाया अधिक महत्वपूर्ण हो गया है ना किसी व्यक्ति की जान बचाना। ऐसा ही मामला जयपुर टैंकर ब्लास्ट के दौरान सामने आया जब एक मैकेनिक आग की चपेट में आ गया। आग की लपटों से घिरने के बाद मोटर मैकेनिक मदद मांगने के लिए 600 मीटर तक पैदल चलता रहा। इस पीड़ित मोटर मैकेनिक की पहचान 32 वर्षीय राधेश्याम चौधरी के नाम से हुई है, जो नेशनल बियरिंग्स कंपनी लिमिटेड में मोटर मैकेनिक थे। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को सुबह-सुबह वे अपनी मोटरसाइकिल से घर से निकले थे। बाद में घटना के बाद की तस्वीरें सामने आईं, जिसमें जलता हुआ एक व्यक्ति मदद की तलाश में चलने के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा था। अखेराम ने कहा, मेरा भाई सड़क पर पड़ा था। लोगों ने मुझे बताया कि वह विस्फोट स्थल से लगभग 600 मीटर दूर चला गया था। वह सड़क पर संघर्ष करते हुए मदद के लिए चिल्ला रहा था। लेकिन मदद करने के बजाय, अधिकांश लोग सिर्फ वीडियो बना रहे थे। भाई और दो पड़ोसी राधेश्याम चौधरी को कार में अस्पताल ले गए, उन्हें एक्सास हुआ कि अफरा-तफरी में एम्बुलेंस का इंतजार करना बेकार होगा। उनके अनुसार, अस्पताल जाते समय उन्हें होश आ गया था और उन्होंने अस्पताल वालों को सारी बातें बताईं, जिसमें एक अजनबी को अखेराम का नंबर देना भी शामिल था, जिसने उन्हें सारी बातें बताईं।

पुष्पा 2 एक्टर अल्लू अर्जुन के घर पर तोड़फोड़, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने लिया हिरासत में

हैदराबाद। उस्मानिया विश्वविद्यालय ज्वाइंट एक्शन कमिटी का सदस्य होने का दावा करने वाले लोगों के एक समूह ने रविवार को यहां अल्लू अर्जुन के घर में फूलों के गमले और अन्य चीजें तोड़ दीं और एक थिएटर में फिल्म 'पुष्पा-2' को दिखाए जाने के दौरान मची भगदड़ में जान गंवाने वाली महिला के लिए न्याय की मांग की। कुछ प्रदर्शनकारी परिसर की दीवार पर चढ़ गए और घर के अंदर टमाटर फेंके। उन्होंने अल्लू अर्जुन के खिलाफ नारे लगाए और मृत महिला के परिवार के लिए एक करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की। प्रदर्शनकारियों के पास मौजूद एक तख्ती पर लिखा था, "फिल्म बनाकर करोड़ों रुपये कमाए जा रहे हैं, जबकि फिल्म देखने वाले मर रहे हैं। 10% पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस सूत्रों ने संकेत दिया कि घटना के समय अल्लू अर्जुन घर पर नहीं थे। उन्होंने बताया कि तोड़फोड़ के मद्देनजर अभिनेता के आवास पर पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। अल्लू अर्जुन के पिता और फिल्म निर्माता अल्लू अरविंद ने कहा कि वे संयम बरतना चाहेंगे और कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा, आपने देखा है कि हमारे घर के बाहर क्या हुआ। लेकिन, यह हमारे लिए संयम बरतने का समय है। हमें इस समय इस सब पर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। पुलिस आई और उन्हें ले गई। उन्होंने मामला दर्ज किया। अगर कोई भी यहां कोई परेशानी पैदा करने के लिए आता है, तो पुलिस उसे ले जाने के लिए तैयार है। किसी को भी इस तरह की घटना को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। हम इसपर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेंगे। कानून अपना काम करेगा। यह एक्शन कमिटी तेलंगाना को राज्य का दर्जा दिलाने के आंदोलन में सबसे आगे रही थी।

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सांसदों की जवाबदेही की वकालत की



नई दिल्ली। संसद में व्यवधान के कारण कामकाज कम होने की पृष्ठभूमि में, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को सांसदों की जवाबदेही की वकालत की और कहा कि लोग सांसदों को यह सोचने पर मजबूर करें कि उन्हें संसद में क्यों भेजा गया। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी लोकतंत्र की सफलता के लिए अभिव्यक्ति और संवाद दोनों बड़ी

जिम्मेदारी के साथ-साथ चलने चाहिए। राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने सांसदों के बीच जवाबदेही का आह्वान करते हुए कहा, "कोई गलती न करें, मैं सांसदों का जिम्मा कर रहा हूँ। लोगों ने अव्यवस्था को व्यवस्था के रूप में लेना सीख लिया है।" आधिकारिक बयान के अनुसार, उपराष्ट्रपति ने कहा, "लोग आपको (सांसदों) सोचने पर मजबूर करेंगे कि आप वहां

(संसद) क्यों गए थे?" चौधरी चरण सिंह पुरस्कार, 2024 के विजेताओं को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि ग्रामीण विकास की रीढ़ है। उन्होंने कहा, "जब तक कृषि का विकास नहीं होता, ग्रामीण परिदृश्य को बदल नहीं जा सकता। और जब तक ग्रामीण परिदृश्य नहीं बदलता, हम विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा नहीं कर सकते।"

अखिलेश यादव के विधायक का विवादित बयान- भाजपा को बता दिया हिंदू आतंकवादी संगठन



लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के सदर विधायक सुरेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर विवादित बयान दिया है। इस बयान के बाद राजनीतिक उथल-पुथल होने की संभावना बनी हुई है। विधायक सुरेश यादव ने भाजपा को हिंदू आतंकवादी संगठन बताया है। समाजवादी पार्टी के विधायक सुरेश यादव का ये बयान चर्चा में बना हुआ है, जिसपर काफी विवाद भी हो रहा है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल है, जिस पर भाजपा कार्यकर्ता आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। बता दें कि बाराबंकी के सदर

इलाके के विधायक सुरेश यादव ने एक बयान दिया है, जिसके बाद वो चर्चा में आ गए हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा को एक हिंदू आतंकवादी संगठन बताया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि ये भाजपा की सरकार नहीं आतंकवादी संगठन है, हिंदू आतंकवादी संगठन। ये पूर्ण रूप से देश को बर्बाद करना चाहती है। ये पार्टी हमारे महापुरुषों के बारे में गलत बातें करेगी। मगर समाजवादी पार्टी इन बयानों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। गौरतलब है कि बाबा साहब भीमवार अंबेडकर को लेकर राजनीतिक बयानों के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने गला संस्थान में विरोध किया था। इस प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री राकेश वर्मा, पूर्व मंत्री और सपा विधायक फरीद महफूज किदवाई ने हिस्सा लिया था। इस प्रदर्शन में ही सपा विधायक सुरेश यादव भी भाषण देने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी को हिंदू आतंकवादी संगठन बताया था।

ललित मोदी चाहते हैं कि बीसीसीआई उनका ईडी जुर्माना अदा करे, कोर्ट ने उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

नई दिल्ली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंडियन प्रीमियर लीग के संस्थापक ललित मोदी पर एक तुच्छ और पूरी तरह से गलत याचिका दायर करने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसमें क्रिकेट नियामक उन पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लगाए गए 10.65 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। मोदी ने कोर्ट से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को मई 2018 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत उल्लंघन के लिए केंद्रीय धन शोधन निरोधक एजेंसी द्वारा उन पर लगाए गए 10.65 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान करने के लिए अंतरिम निर्देश मांगा था। हालांकि, जस्टिस एमएस सोनक और जितेंद्र जैन की पीठ ने 2005 के सुप्रीम कोर्ट के एक

फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार बीसीसीआई 95% की परिभाषा में नहीं आता है। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के स्पष्ट आदेशों के बावजूद, मोदी ने 2018 में यह याचिका दायर की थी। पीठ ने कहा, ईडी द्वारा याचिकाकर्ता (मोदी) पर लगाए गए जुर्माने के संदर्भ में याचिकाकर्ता (मोदी) की कथित क्षतिपूर्ति के मामलों में, किसी भी सार्वजनिक कार्य के निर्वहन का कोई सवाल ही नहीं है, और इसलिए, इस उद्देश्य के लिए, बीसीसीआई को कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है। इसने कहा, किसी भी स्थिति में, राहत पूरी तरह से गलत है। फेमा के तहत न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता पर 10.65 करोड़

रुपये का जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को यह राशि चुकाने के लिए बीसीसीआई पर परामर्श की रिट चाहता है। ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता।

देश चिकित्सकों की कमी का सामना कर रहा, मेडिकल सीटें बर्बाद नहीं होनी चाहिए : उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि ऐसे समय में जब देश डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहा है, "कीमती" मेडिकल सीटें बर्बाद नहीं होनी चाहिए। न्यायालय ने प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे रिक्त सीटों को भरने के लिए नये सिरे से काउंसिलिंग आयोजित करें। न्यायमूर्ति वी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने दाखिल देने वाले प्राधिकारियों को विशेष काउंसिलिंग आयोजित करने और 30 दिसंबर तक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने को कहा। पीठ ने आदेश दिया, "विशेष तथ्यों और परिस्थितियों तथा इस बात पर ध्यान रखते हुए कि देश डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहा है, बहुमूल्य मेडिकल सीटें व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, हम अंतिम अवसर के रूप में अवधि बढ़ाने के लिए इच्छुक हैं।"

मोहाली में गिरी इमारत, मचा हड़कंप, दो की हुई मौत

पंजाब। पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) जिले के सोहाना गांव में बहुमंजिला इमारत गिरने के स्थान से रविवार सुबह एक शव बरामद किया गया। इसके साथ ही इस घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर दो हो गई। इससे पहले, बचाव दल ने इमारत के मलबे में फंसे लोगों की तलाश में रात भर काम किया, जो शनिवार शाम को ढह गई थी। रविवार सुबह घटनास्थल से प्राप्त दृश्यों में भारतीय सेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के जवान बचाव अभियान जारी रखते हुए दिखाई दिए। पहली पीड़ित 20 वर्षीय महिला हिमाचल प्रदेश की थी, जबकि दूसरा पीड़ित पुरुष हरियाणा के अंबाला का था। पुलिस ने बताया कि चार मंजिला इस इमारत के बेसमेंट में जिम था, जो इमारत के मालिकों द्वारा बगल के भूखंड पर किए जा रहे खुदाई कार्य के कारण ढह गई। पुलिस के अनुसार, खुदाई के कारण जमीन धंस गई और उसके साथ ही इमारत भी गिर गई। मालिक परविंदर सिंह और गगनदीप सिंह पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिला अधिकारियों ने एक नियंत्रण कक्ष फोन नंबर (0172-2219506) जारी किया है।

बी पी एस न्यूज परिवार की ओर से सभी देशवासियों को हैप्पी क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं



सम्पादक (बी.पी.साहू)
मो.8423454502,
9335908846

बी पी एस न्यूज लेटेस्ट खबरें पढ़ने व देखने के लिए लॉगिन करें
www.bpsnews.in

संपादकीय

असंसदीय कृत्य

जब देश की नई संसद में सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तो विश्वास था कि देश में संसदीय मर्यादाओं को नई गरिमा मिलेगी। लेकिन हाल ही में संपन्न शीतकालीन सत्र के दौरान हुए हंगामे ने देश के आम जनमानस को गहरे तक निराश ही किया। सड़क पर सांसदों की धक्का-मुक्की और आरोप-प्रत्यारोपों ने उन मतदाताओं को ठेस पहुंचाया, जिन्होंने उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना था। आरोप-प्रत्यारोप तो सांसदों की पुरानी परंपरा रही है, लेकिन इस बार तो बात धक्का-मुक्की से लेकर थाने तक जा पहुंची। ऐसे में सवाल किया जा सकता है कि जब हमारे माननीयों का व्यवहार ऐसा होगा तो आम आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है। दरअसल, महाराष्ट्र चुनाव में करारी शिकस्त से परत विपक्ष सरकार पर हमले के लिये मुद्दे की तलाश में था। उन्हें मुद्दा खुद गृहमंत्री अमित शाह ने दे दिया। संविधान के रचयिताओं में अग्रणी डॉ. बी.आर. अंबेडकर के बारे में शाह की टिप्पणी के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन के सांसदों के बीच आरोप-प्रत्यारोपों का सिलसिला कालांतर टकराव में बदल गया। निश्चय ही राजनेताओं के व्यवहार से देश-विदेश में कोई अच्छा संदेश नहीं गया। जिन सांसदों के हाथ में कानून की गरिमा बनाये रखने की जिम्मेदारी है, वे हाथ ही धक्का-मुक्की में लिस होने लगे। जो जनप्रतिनिधियों की कथनी-करनी के अंतर को ही दर्शाता है। सही मायनों में यह मतदाताओं का भी अपमान है जिन्होंने उन्हें चुनकर संसद में भेजा है। निस्संदेह, जब अमित शाह ने कहा कि डॉ. अंबेडकर का नाम जपना एक फैशन बन गया तो ऐसा करके उन्होंने अपना कद कदापि नहीं बढ़ाया। इस तरह उन्होंने संविधान के जनक को एक अनावश्यक विवाद में घसीट लिया। महाराष्ट्र चुनाव में पराजय के बाद खस्ता हाल में आये विपक्ष को इस विवाद ने राजग पर एकजुट हो हमलावर होने का अवसर दे दिया है। विपक्ष ने भी मुद्दे को तुरंत लपक लिया। लेकिन इस तरह के विवाद को असंसदीय ही कहा जाएगा। कालांतर में स्थिति यहां तक पहुंच गई कि शाह की बयानबाजी के बचाव में खुद प्रधानमंत्री को उतरना पड़ा। उन्होंने कांग्रेस पर राजनीतिक स्वार्थ के लिये दुर्भावनापूर्ण झूठ का सहारा लेने का आरोप भी लगाया। निस्संदेह, डॉ. बी.आर. अंबेडकर एक ऐसे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जिनकी गरिमा को कोई भी राजनीतिक पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। यह स्पष्ट ही है कि राजनीतिक लाभ के लिए दोनों प्रमुख पार्टियां उनकी विरासत पर कब्जा करने को यह खेल खेल रही हैं। उनका अमर्यादित व्यवहार इस स्थिति को और गंभीर बना देता है। विडंबना ही है कि ये स्थितियां तब पैदा हुईं जब देश संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह आयोजित कर रहा था। दुनिया को यह बताने का प्रयास कर रहा था कि लोकतंत्र, न्याय और समानता की कसौटी पर यह जीवंत दस्तावेज खरा उतरा है। निस्संदेह, इस बात में दो राय नहीं हो सकती कि संविधान के आदर्शों को बनाये रखना सभी सांसदों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

एक साथ चुनाव की आकांक्षा से परे भी देखें

सांसद इस पर विचार कर सकते हैं कि क्या लोगों के अधिकारों को ऐसे तोड़ना-मरोड़ना लोकतंत्र का चरित्र हनन नहीं? यह द्वैत बनाने से क्या हासिल होगा? क्या एक साथ चुनाव इतना पवित्र उद्देश्य है या फिर लोकतांत्रिक विकल्प प्रदान करने वाले मौलिक सिद्धांत को प्रबंधकीय दक्षता बनाने के अधीन बना दिया जाए? कानून निर्माताओं की समझ की परीक्षा हो रही है। आखिरकार, संविधान निर्माताओं ने एक साथ चुनाव कराने का प्रावधान नहीं किया और किसी आपातकालीन स्थिति की अनिवार्यताओं से निबटने के लिए, संवैधानिक ढांचे के भीतर रहते हुए, इस पर निर्णय का काम भारत के चुनाव आयोग पर छोड़ दिया। कोई भी व्यक्ति एक लघु, त्वरित, एकल पूर्वानुमानित



बेशक 'एक देश-एक चुनाव' की व्यवस्था के कई फायदे हैं लेकिन दशकभर बाद लागू होने वाले देश कानून को लेकर सत्तापक्ष की जल्दबाजी 'दिलचस्प' है। क्या चुनाव कराने में दक्षता से महत्वपूर्ण और मुद्दे देश के सामने नहीं हैं। यूं भी सरकार के पक्ष में या खिलाफ मतदान का अधिकार लोकतंत्र का अनिवार्य तत्व है। मौजूदा व्यवस्था में भी इतनी तो लोच है कि चुनाव आयोग कुछ इलेक्शन एक साथ करवा सकता है। मतदाता और निर्वाचित प्रतिनिधि के बीच संबंध मांग और आपूर्ति जैसा है। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनकर आए प्रतिनिधि वोटर की आकांक्षाओं की पूर्ति करने की दिशा में काम करते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी जहां अपने चुनावी वादों पर अमल करने की कोशिश करती है वहीं कभी-कभी अपना वह दृष्टिकोण लागू करने को काम करती है, जो उसके हिसाब से लोगों और देश के लिए अच्छा है। एक राष्ट्र-एक चुनाव का संकल्प भाजपा के चुनाव घोषणापत्र का हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन समाज के किसी भी वर्ग द्वारा इसकी मांग नहीं की गई थी, हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि भारत 'बहुत अधिक लोकतंत्र' से ग्रस्त है। किंतु, सत्तारूढ़ पार्टी 'एक देश-एक चुनाव' की खूबियां को लेकर काफी आश्चर्य है, यह उसके नेतृत्व द्वारा बार-बार किए दावों और जिस प्रकार का मसौदा राम नाथ कोविंद समिति बनाते वक सौंपा गया था, उससे स्पष्ट है। इसकी सिफारिशें पहले से तय निष्कर्ष हैं, लेकिन जिस तेजी से सरकार ने इस पर काम किया, उसने कई लोगों को चौंकाया। खंडित जनादेश से टिकी एनडीए सरकार से बहुत कम लोगों को उम्मीद थी कि वह इस मामले को इतनी शिद्दत से आगे

बढ़ाएगी, खासकर जब इस पर कार्यान्वयन होना दूर की कौड़ी है। एक व्यवस्था जो एक दशक बाद लागू होनी है, उस पर कानून बनाने की सरकार की जल्दबाजी वाली 'दूरदर्शिता' दिलचस्प है। साल 2024 के आम चुनाव से पहले महिला आरक्षण विधेयक (नारीशक्ति वंदन अधिनियम) पारित करने में इसी किस्म की तत्परता दिखाई थी। फर्क यह कि महिलाओं वाला विधेयक पारित करने में सभी पक्ष एकमत थे, वहीं 'एक देश-एक चुनाव' संबंधी 129वें संविधान संशोधक विधेयक की वांछनीयता पर मतभेद हैं। सरकार को विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजने में आपत्ति नहीं हुई क्योंकि उसे पता था इससे विपक्ष संतुष्ट होगा और उसकी अपनी खुली सोच झलकेगी। जल्दबाजी में विधेयक पारित करना उद्देश्य नहीं हो सकता, इसे पटल पर लाना और आम सहमत की संभावना खोलना महत्व है ताकि लगे कि वे 'बड़े' चुनावी सुधार पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा है? संविधान में इस आशय का स्पष्ट प्रावधान हुए बिना, 1951 के बाद से, 15 वर्षों तक देशभर में चुनाव एक साथ होते रहे। लेकिन सत्ता राजनीति के उतार-चढ़ाव और गतिशीलता के कारण यह शृंखला टूट गई। किसी सरकार के पक्ष में या खिलाफ वोट का हक लोकतंत्र का अनिवार्य तत्व है। बेशक यह विधेयक सत्तारूढ़ पार्टी को दिया समर्थन वापस लेने का हक नहीं छीनता, लेकिन मतदाताओं को ऐसी सरकार चुनने का 'हक' देता है, जो बीच कार्यकाल सदन में बहुमत खोने के बावजूद बाकी अवधि के लिए राज करती रहे। इस प्रकार, एक

निवर्तमान निर्वाचित शासन सीमित अवधि के लिए आगामी निर्वाचित विकल्प हेतु मार्ग प्रशस्त करेगा। इस तरह, सब चुनाव एक साथ करने के शौक में मतदाता पांच साल में एक बार खेलने को ऐसी टीम (सरकार) चुनेंगे जिसके मुख्य खिलाड़ी (सरकार) चोटिल होने (बहुमत खोने) के बावजूद वह एक्सट्रा या नाइटवॉचमैन के रूप में शासन करती रहे। इस प्रकार, उपचुनाव में किसी संसद या विधानसभा सदस्य को चुनने के लिए जो प्रणाली अब लागू है, तब वह मध्यावधि चुनाव की स्थिति बनने पर पूरे सदन के लिए लागू हो जाएगी। चुनाव कराना नियमित लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन यह यूपीएससी परीक्षा की तरह नहीं, जो एक तय कार्यक्रमानुसार, साल में एक बार सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। प्रशासनिक दक्षता वांछनीय है और ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनसे चुनाव संचालन कम वक खपाऊ और कम मानव संसाधन इस्तेमाल करने वाला बन सके। अर्धसैनिक बलों पर अत्यधिक निर्भरता, जिनकी उपलब्धता का वास्ता देकर चुनाव आयोग लंबी अवधि चलने वाला बहु-चरणिय चुनाव करवाना मजबूरी गिनाता आया है, हमारी राजनीति की अस्थिर प्रकृति के कारण है। मौजूदा कानून चुनाव आयोग को किसी भी सदन का कार्यकाल समाप्त होने से छह माह पहले चुनाव कराने का अधिकार देता है, जिससे उसे कुशल प्रबंधन के लिए कुछ चुनाव एक साथ कराने में कुछ लचीलापन मिल जाता है। हालांकि, हालिया उदाहरण हैं कि चुनाव आयोग ने उन चुनावों को भी

अलग-अलग करवाने का विकल्प चुना, जिन्हें आसानी से एक साथ करवा सकता था। स्पष्टतया, एक साथ चुनाव लागू करवाने पर दिखाई जाने वाली जल्दबाजी के पीछे सिद्धांत कम और मनमानी ज्यादा है। यह तथाकथित सुधार संसद में पारित हो या न हो, अब समय है कि सरकार और राजनीतिक दल पैसा, अपराध, जाति, समुदाय, चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी, उम्मीदवारों की अयोग्यता और चुनाव खर्च सीमा तय करने जैसे मुद्दों संबंधी ठोस चुनावी सुधारों को आगे बढ़ाए/जिनका सुझाव चुनाव आयोग ने भी दिया है और लांबित हैं। एक साथ चुनाव करवाने का उद्देश्य चुनावों पर सरकारी खर्च कम करना बताया जा रहा है, लेकिन चुनावों में काले धन का इस्तेमाल रोकने और राजनीतिक फंडिंग के पारदर्शी तरीके खोजने के बारे में क्या? नया विधेयक तथाकथित सुधारों के जरिये इन पर ध्यान केंद्रित करने को नहीं कह रहा। सनद रहे, आदर्श आचार संहिता केवल एक निश्चित श्रेणी के सार्वजनिक व्यय पर रोक लगाती है, ताकि सत्तारूढ़ दल को सरकारी संसाधन खर्च कर अनुचित लाभ न मिले। हेरानु ही यह कि सत्तारूढ़ दल प्रमुख नीतिगत निर्णय लेने को चुनावों से ऐन पहले तक इंतजार क्यों करते रहते हैं और फिर उन्हें 'शासन में बाधा डालने वाला' कहते हैं। इससे आगे, किसी भी राज्य में चुनाव के मुद्दे उस सूबे के मतदाताओं और राजनीतिक नेताओं से संबंधित होते हैं, इनका असर न दूसरे राज्यों के मतदाता पर होता है।

शाबाश ऑफिसर! - ऑफिस में बुजुर्ग शख्स को इंतजार करवाया

गोंदिया। वैश्विक स्तर पर भारत को बौद्धिक क्षमता का धनी माना जाता है, परंतु भ्रष्टाचार स्वाथ्र मलाई कामचोरी व जनता को चकरे खिलाने में माहिर करीब सभी कार्यालयों के अनेकों कर्मचारी अपनी बौद्धिक क्षमता का गलत इस्तेमाल अपने, निजी आरामदायक सुविधाओं के लिए चंद्र रूप्यों के लिए आम जनता, विशेष रूप से बुजुर्गों को भी अपनी टेबल के चकरे खिलाने में माहिर होते हैं, जो देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, इसका अनुभव मैंने स्वयंम में भी अनेकों शासकीय कार्यालय में चकरे खाकर महसूस किया हूँ कि करीब करीब हर अधिकारी चकरे खिलाने में माहिर होता है। हमारा पीएम या पूरा मंत्रिमंडल चाहे कितनी भी बातें भ्रष्टाचार के खिलाफ कर लें परंतु जमीनी स्तर पर असर अभी भी कम नहीं हो रहा है। चंद्र रूप्यों याने चाय पानी के लिए टेबल के 10 चकरे खाना ही पड़ता है या फिर मजबूरी से किसी दलाल के थरु काम करना पड़ता है जो अत्यंत ही चिंताजनक है, जो हमारे पीएम के सपनों को चकनाचूर करने में लगे हुए हैं। इस लिए इस आर्टिकल के माध्यम से मैं 20 दिसंबर 2024 तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में एक विधेयक अधिसूचित करने का सुझाव देता हूँ जो सीधा ऑफिस के टेबलों के चकरे खिलाने वाले बाबुओं कर्मचारियों और अधिकारियों अधीक्षकों व सीईओ को द्वारा सीसीटीवी कैमरे में देखकर भी कुछ एक्शन नहीं लेकर मूक दर्शक बने रहते हैं उनके खिलाफ भी सीधे केस दर्ज करवा कर निर्वाचित कर देने का प्रावधान सहित संपूर्ण आचार संहिता को धाराओं को शामिल कर विधेयक को यदि इस शीत सत्र में पेश करना संभव नहीं हो तो, पूरे तैयारी के साथ अगले वर्ष 2025 के बजट सत्र में पेश किए जाने की सख्त जरूरत है। आज हम इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिनांक 17 दिसंबर 2024 को पूरे सोशल मीडिया में एक क्लिप बहुत ही तीव्र गति से सर्कुलेट हो रही है जिसमें बुजुर्ग कोई फाइल क्लीयर कराने के लिए एक ऑफिस में चकरे काटने पड़ रहे हैं, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है इतना तक कि अधीक्षक या सीईओ या बॉस ने सीसीटीवी में देखकर संबंधित कर्मचारियों को बिदायत देने के बावजूद उस बुजुर्ग का काम नहीं हुआ तो बॉस ने पूरे स्टाफ को एक अनोखी सजा दी, जिसका संज्ञान पूरे भारत के शासकीय व निजी अधिकारियों या बॉस ने लेना समय की मांग है। इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से व उपलब्ध इमेज का



प्रयोग करके इस आर्टिकल के माध्यम से चुनौतियों, सरकारी कार्यालयों में छोटे-छोटे कामों के लिए कर्मचारियों द्वारा जनता को चकरे खिलाने वाले कर्मचारियों के लिए सजा का अध्यादेश लाना जरूरी है। साथियों बात अगर हम सोशल मीडिया में 17 दिसंबर 2024 शाम से वायरल एक क्लिप को करें तो, दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा से अनोखा मामला सामने आया है। वहां के सीईओ ने कर्मचारियों को लापरवाही पर कड़ा एक्शन लेते हुए आवासीय भूखंड विभाग के स्टाफ को आधे घंटे तक खड़े होकर काम करने का फरमान सुना दिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वह चैनलों के अनुसार के अनुसार एक बुजुर्ग दंपती अपनी समस्या के समाधान के लिए प्राधिकरण के आवासीय भूखंड विभाग पहुंचे थे, लेकिन घंटों इंतजार के बावजूद उनका काम नहीं हो सका, जिसके बाद सीईओ ने कर्मचारियों को ये सजा सुनाई दरअसल, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने अपने ऑफिस में एक सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन पर बुजुर्ग दंपती को काफी देर तक खड़े देखा जो आवासीय भूखंड विभाग को निर्देश दिया कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन उसके बावजूद 15-20 मिनट बाद जब सीईओ ने फिर से सीसीटीवी पर नजर डाली तो बुजुर्ग दंपति तब भी खड़े दिखे, इस पर नाराज सीईओ आवासीय विभाग पहुंचे और कर्मचारियों को लापरवाही पर कड़ी फटकार लगाई। सीईओ ने कर्मचारियों को कहा, जब आप खड़े होकर काम करेंगे तभी बुजुर्गों की परेशानी को समझ पाएंगे। इसके बाद उन्होंने सभी कर्मचारियों को आधे घंटे तक खड़े होकर काम करने का निर्देश दिया। निर्देश के अनुसार, स्टाफ ने खड़े होकर काम किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर हो रही है तारीफ - कर्मचारियों को लापरवाही के लिए दी गई सजा की हर तरफ तारीफ की जा रही है। लोग इस पर अलग-अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं। कई लोगों की कहना है कि इस तरह अफसर यदि कर्मचारियों को सजा दें तो कर्मचारी अपने काम के प्रति लापरवाह नहीं रहेंगे। साथियों बात अगर हम बुजुर्गों के लिए एक एक्सट्रासिटी के समकक्ष कानून, सूचीगत जातियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 2019 के समकक्ष बुजुर्गों के सम्मान के लिए कानून बनाने की करें तो जिस तरह सामाजिक

सौहार्दपूर्णता समानता को कायम रखने के लिए एस्ट्रासिटी (अमेंडेड) कानून 2019 बनाया गया है जिसका डर हमेशा उपद्रवी लोगों में बना रहता है या फिर कभी नए फौजदारी अधिनियम 2023 में क्राइम को रोकने अनेक धाराओं का डर लोगों में बना हुआ है उसी तर्ज पर मेरा सुझाव है कि लोकसभा के शीतकालीन सत्र या फिर अगले महीने 2025 के बजट सत्र में बुजुर्गों के साथ होने वाली क्रूरता दुष्परिणाम दुर्व्यवहार अपमान व दुल्कार पर लगायत लगे के लिए वरिष्ठ नागरिक (अत्याचार अपमान दुर्व्यवहार व्यवहार व दुराचार) विधेयक 2024 बनाकर पेश किया जाए जिसे सभी पार्टियों एक मत होकर 544/0 मतदान से पारित करेंगे ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। साथियों बात अगर हम 20 दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाले शीत सत्र या जनवरी 2025 के चौथे सप्ताह से शुरू होने वाले बजट सत्र में प्राथमिकता से इस विधेयक को अधिसूचित करने की करें तो, हम प्रस्तावित कानून में वरिष्ठ नागरिक (कार्यालयों में चकरे खिलाना अत्याचार अपमान दुर्व्यवहार निवारण) विधेयक 2024 की जरूरत है, हमारा देश महान संतानों की भूमि है, यहां शासकीय व निजी कार्यालयों में बुजुर्गों दिव्यांगों व सामान्य नागरिकों की उचित देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन पीड़ादायक है कि नैतिक मूल्यों में इस कदर गिरावट आ गई है कि अपना सुख-चैन व भ्रष्टाचार के बल पर, अपने परिवार को आरामदायक जिंदगी देने आम नागरिकों को अपने कार्यालय में टेबल के चकरे काटने के लिए छोड़ देते हैं, जो न सिर्फ दुखद है, बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों में निरंतर आ रही गिरावट का प्रतीक भी है हमारे सामाजिक मूल्यों में तेजी से आ रहे बदलाव की वजह से आज बुजुर्गों को अपने छोटे-छोटे कामों के लिए शासकीय कार्यालय के चकरे काटने, वरना काम नहीं होने पर अदालतों की शरण में आना पड़ रहा है, इस तरह की उद्देश्य शासकीय कर्मचारियों को सजा के रूप में आदेश भी अदालत दे रही हैं, लेकिन यह सिलसिला बदस्तूर जारी है सामाजिक मूल्यों में आ रहे ह्रास का ही नतीजा है कि दर बंदर की ठोकरें खाने के लिये छोड़ दिया जा रहा है या फिर सुरक्षित व जल्द काम करने के लिए हरे पीलों की अपेक्षा की जाती है, लेकिन पीड़ादायक है कि नैतिक मूल्यों में इस कदर गिरावट आ गई है।

केशन सनमुखदास भाववानी

कायस्थ महासमागम में वनमंत्री ने समागम में दीप

प्रज्ज्वलित कर किया शुभारंभ

-दूरदृष्टी, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, ईमानदारी इन चार चीजों से लक्ष्य हासिल किया जा सकता : मंत्री अरुण



दूरदृष्टी, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, ईमानदारी इन चार चीजों से लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा- कायस्थ समाज का अतीत

बहुत गौरवशाली रहा है, हमारे समाज में बहुत-बहुत बड़े-बड़े लोगों को जन्म दिया है। अध्यात्म के क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद का नाम किसी परचिम के मोहताज नहीं है, शिकागो में स्वामी विवेकानंद की स्पीच व धर्म के प्रचार का किया उसका कोई

मुकाबला नहीं है। समाज सेवा में राजाराम मोहन राय ने सती प्रथा पर रोक लगाई। उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र का कोई सानी नहीं है, उन्होंने दिल को छूने वाले प्रेरणादायक उपन्यास लिखे। आर्यभट्ट, सीवोरमन जैसे वैज्ञानिक देश को कायस्थ समाज ने दिए। उन्होंने कहा 1952 के यूपी असंबली के पहले चुनाव में कायस्थ समाज के 50 विधायक थे, वहीं 2022 के चुनाव में मात्र तीन विधायक कायस्थ समाज के बचे। भाजपा ने उप चुनाव में कायस्थ वर्ग के दो सदस्य जीत कर आने के बाद समाज के

विधायकों की संख्या पाँच हो गई है। सरकारी नौकरियों में समाज के 40 प्रतिशत लोग थे, आज उनकी संख्या 4 प्रतिशत बची है। वन मंत्री अरुण सक्सेना ने दीप प्रज्ज्वलित कर समागम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम संयोजक व राष्ट्रीय अध्यक्ष मयंक श्रीवास्तव व समेत कायस्थ समाज के लोगों ने मुख्य अतिथि अरुण सक्सेना का सम्मान किया। समागम में वन मंत्री ने रस्मारिका का विमोचन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मयंक श्रीवास्तव ने बताया कि समागम का मुख्य उद्देश्य समाज के लोगों को एकजुट करना व परिवार के बच्चों को स्वरोजगार मुहैया कराया जा सके। उन्होंने कहा कि बच्चों को नौकरी मांगने के बजाए नौकरी देने वाला कैसे बने।

नहर की सफाई में फटी गैस पाइप लाइन मचा हड़कंप, सप्लाई की गई बंद

कानपुर। दादा नगर पनकी साइट-5 में नहर की सफाई के दौरान सीयूजीएल की पाइप लाइन फट गई। पोकलैंड मशीन जैसे ही नहर की तली तक पहुंची लाइन से गैस रिसने से बड़ा फव्वारा उठने लगा। इंडस्ट्रियल क्षेत्र में गैस पाइप फटते ही हड़कंप मच गया। आनन-फानन में लीकेज को बंद कर आपूर्ति सामान्य की गई। आनन-फानन में सिंचाई विभाग ने सीयूजीएल के इमरजेंसी नंबर पर फोन किया। जिसके बाद मौके पर पहुंची सीयूजीएल टीम ने सप्लाई को बंद कर मरम्मत कार्य शुरू कर दिया। इस दौरान नहर का पानी पूरी तरह से रोक दिया गया। देर शाम को सीयूजीएल की टीम ने पाइप लाइन की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया। इस दौरान पाइप से गैस की सप्लाई पूरी तरह से बाधित रही। सिंचाई विभाग नहर की सफाई कर रहा है। औद्योगिक क्षेत्र पनकी साइट 5 में पुल के पास विभाग सफाई करवा रहा था। पोकलैंड मशीन जैसे ही नहर की तली में सफाई करने पहुंची यहाँ नहर के नीचे से कई सीयूजीएल की पाइप लाइन फट गई। इस दौरान गैस पानी के साथ मिलकर फव्वारे में बदल गई। काफी देर तक अधिकारी यह समझते रहे कि कोई पेयजल व अन्य लाइन फटी है। लेकिन, जब पता चला कि यह गैस पाइप लाइन है अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में सीयूजीएल के इमरजेंसी नंबर पर फोन कर पाइप लाइन फटने की जानकारी दी गई। सिंचाई विभाग के जेई गोविंद ने बताया कि सीयूजीएल ने सिंचाई विभाग से बिना एनओसी लिये ही नहर के नीचे से मशीन द्वारा गैस लाइन निकाल दी है। जिसकी जानकारी नहर विभाग को नहीं है। उन्होंने बताया कि विभाग ने गैस पाइप का कोई बोर्ड भी नहीं लगाया है। नहर की सफाई के दौरान पाइप लाइन फट गई है, बड़ा हादसा होने से बचा है। सहायक अभियंता अजय राव ने बताया कि आस-पास के लोगों से जानकारी में पता चला कि 2011 में यह पाइप लाइन डाली गई है। इसको लेकर सीयूजीएल को नोटिस दी जा रही है।

अपनी समस्या हमें बतायें

आपके साथ या आपके आस-पास कोई घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, जर्म हुआ है या उत्पीड़न हुआ है अथवा आपके क्षेत्र की समस्या है और आपकी समस्या जायज है तो आपकी समस्याओं के समाधान हेतु सम्बन्धित उच्च अधिकारियों एवं शासन-प्रशासन तक पहुंचाने के लिये बी पी एस न्यूज आपके साथ है। आपकी खबर शत्रु प्रतिशत प्रकाशित की जायेगी। एवं आपका नाम व नम्बर आपके अनुसार प्रकाशित या पूर्णतया गुप्त रखा जायेगा। दिये गये नम्बर पर काल करें या हमें ई मेल करें। फोन नं.- 8423454502, bps.knp786@gmail.com

आवश्यक सूचना

प्रिय ग्राहकों/विज्ञापनदाताओं को सूचित किया जाता है कि बी.पी.एस. न्यूज समाचार पत्र में नगद भुगतान की व्यवस्था नहीं है। कृपया चेक/डी.डी. बी पी एस न्यूज के नाम से ही चेक आदि भेजें। नगद भुगतान की व्यवस्था नहीं है। नगद भुगतान करने पर विज्ञापनदाता स्वयं जिम्मेदार होंगे। - संपादक

आवश्यकता है

बी पी एस न्यूज राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक, साप्ताहिक समाचार पत्र व ऑनलाइन न्यूज चैनल (पोर्टल) के लिये समस्त तहसीलों एवं ब्लॉक स्तर पर ब्यूरो चीफ, संवाददाताओं, छायाकार तथा विज्ञापन प्रतिनिधियों युवक-युवतियों की आवश्यकता है। संपादक मो. : 8423454502 email: bps.knp786@gmail.com

महिलाओं ने चमन बना दिए शहर के तीन रैन बसेरे

–नगर निगम के चुन्नीगंज, कल्याणपुर और सुतरखाना आश्रय गृहों को चमकाया तीन महिला संचालिकाओं ने

बीपीएस न्यूज

कानपुर। कहते हैं महिलाओं के हाथों में वो बरकत होती है जो मकानों को घर बना देती हैं। कानपुर महानगर में तो महिलाओं ने सरकारी भवनों को भी सजा-संवार कर रहने योग्य बसेरा बना दिया है। हम बात कर रहे हैं सरकारी आश्रय गृहों की। महानगर में नगर निगम द्वारा संचालित दो दर्जन से अधिक आश्रय गृहों, यानी रैन बसेरों में से केवल 3 ही संचालन के लिए महिलाओं को दिए गए हैं। लेकिन इन तीन महिलाओं ने साबित कर दिया कि वो वाकई दो से तीन माले की रैन बसेरों की इमारतों की छटा और फिजा बदलने में सक्षम हैं।

शहर के बीचों बीच, जोन 4 में चुन्नीगंज इंटरस्टेट बस अड्डे के सामने स्थित तीन माले के सरकारी रैन बसेरा में जनता ने यही बड़ा बदलाव देखा। बस अड्डे के आसपास के दुकानदारों, इलाकाई

लोगों आदि का कहना है कि जबसे इस रैन बसेरा का चार्ज एक महिला को दिया गया यहाँ की फिजा ही बदल गई है। चाय का होटल चलाने वाले लखनऊ निवासी सुनील तिवारी कहते हैं पहले जहाँ चुन्नीगंज रैन बसेरा में शराबियों और अराजकतत्वों के डेरा जमा लेने की शिकायतें मिलती थीं, अब वहीं हर निराश्रित चुन्नीगंज रैन बसेरा में रात में सुरक्षित महसूस करता है। अब ना सामान चोरी का डर है और ना ही गंदे गंदे, चादरों और लिहाफ़ों की दिक्रत है। शहर में रोजगार करने वाले बेनारस निवासी अमर कुमार और इलेक्ट्रिशियन फैजान अली कहते हैं कि काम से लौटते पर देर हो जाने के चलते अक्सर उनको रात में रैन बसेरा में रुकना पड़ता था। चोरी के डर से रात में औजारों को बिस्तर पर साथ लेकर सोते थे। लेकिन अब उसी रैन बसेरा में घर जैसा आराम, सुकून और सुरक्षा

महसूस होती है। वहाँ की संचालिका द्वारा साफ सफाई से लेकर सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगावा देने, शराबियों, अराजकतत्वों और आवारा जानवरों को अंदर घुसने से रोकने के पुख्ता इंतजाम कर दिए जाने से सब सुरक्षित हैं। रैन बसेरा के सामने दशकों से नारायण स्वीट्स के नाम से दुकान चलाने वाले %ठाकुर अंकल% कहते हैं कि रैन बसेरा में अब सुरक्षा और सुकून है। नगर निगम बड़े संख्या में महिलाओं को रैन बसेरों में रुकने वालों और उनके साजो-सामान के सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। इसलिए साफ-सफाई के साथ ही सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। अनीता त्रिपाठी के अनुसार आश्रय गृह में इस काम में वो जो कुछ कर सकीं, उसमें कानपुर की मेयर प्रमिला

पांडेय का बड़ा सहयोग है। महिला होने के नाते उनका सहयोग हमेशा रहता है। रंग-रोगन से लेकर संसाधन जुटाने और साजसज्जा तक में नगर निगम अधिकारियों का बड़ा सहयोग रहा।

वहीं कल्याणपुर और सेंट्रल स्टेशन से सटे सुतरखाना आश्रय गृह की संचालिकाओं ने भी बेहतरीन मैनेजमेंट का उदाहरण पेश किया है। जोन 5 स्थित कल्याणपुर रैन बसेरा संचालिका अनीता भदौरिया कहती हैं कि महिला होकर जनता के बीच काम करते हुए गर्व की अनुभूति होती है।

इस बात की संतुष्टि होती है कि प्रशानिक सहयोग से गरीबों के हित में कुछ अर्थपूर्ण कार्य कर रहे हैं। जोन 1 स्थित सूत्रखाना आश्रय गृह की संचालिका संध्या सिंह कहती हैं कि संचालन में प्रयास करती हैं की सरकारी गाइडलाइन को पूरी तरह फॉलो करें। अगर

किसी रुकने वाले के पास आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र नहीं है तो उसका फोटो खींच कर रिकॉर्ड रखते हैं। सर्दियों में साफ बिस्तर, कंबल और लिहाफ आदि रुकने वालों को मिले, यही कोशिश रहती है। संध्या भी कहती हैं कि गरीबों और जरूरतमंदों को रुकने सोने का सुरक्षित स्थान उपलब्ध करने का ये काम जीवन में एक उद्देश्य और

शराबियों और गदाईयों को काबू करना मुश्किल
विवृत 6-7 वर्षों से रैन बसेरों का संचालन कर रही महिलाओं की दो कॉमन समस्याएं हैं। वो हैं इलाकाई अराजकतत्व और नशेड़ी, जो जबरन रैन बसेरे में घुसकर ना

सिर्फ गंदगी फैलाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए खतरा भी पैदा करते हैं। उनको किसी तरह अपने केयरटेकरों के साथ मिलकर समझा कर वापस भेजते हैं। वहीं सरकार के निर्देश हैं कि सर्दी में कोई भी सड़कों पर ना सोए। लेकिन भिखारी और गदाई किसी भी तरह रैन बसेरा में अंदर रुकने को तैयार नहीं होते। क्योंकि बाहर सड़क पर सोने से उनको रोजाना फ्री के कंबल और ढेरों ढेरों रुपए दान या धीख में मिल जाते हैं। ऐसे में भिखारियों को सड़क से किसी तरह रैन बसेरा में पकड़ कर भी लाए तो एक दिन से अधिक रुकते नहीं। अंदर बाकियों के लिए साफ सफाई की समस्या उत्पन्न करते हैं।

पुलिस प्रशासन द्वारा नेता को किया हाउस अरेस्ट

कानपुर। प्रदेश में धारा 163 बी एन एस लागू होने के बावजूद कांग्रेस नेता सूरज शर्मा ने लखनऊ विधानसभा धरना प्रदर्शन का किया समर्थन कानपुर से काफ़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं ने लखनऊ विधानसभा पर धरना प्रदर्शन करने की बनाई थी योजनागोपनीय सूचना पर जानकारी प्राप्त होते ही रावतपुर थाना प्रभारी ने कांग्रेस नेता को किया हाउस अरेस्ट रावतपुर थाना पुलिस प्रशासन द्वारा कांग्रेस नेता को दिया गया नोटिस व चेताया कि कानूनी नियमों का उल्लंघन करने पर की जाएगी अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही बीते दिन देर शाम से ही बिना कोई हानि पहुंचाए सूरज नेता को कानपुर पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया ।

अपनी माँगों को लेकर काली पट्टी बाँध किया एक घंटे अतिरिक्त कार्य



बीपीएस न्यूज

कानपुर। विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर पूरे प्रदेश के बिजली संविदा कर्मचारियों ने अपनी वेतन बढ़ोतरी सहित चार माँगों को लेकर काली पट्टी बाँधकर एक घंटे अतिरिक्त कार्य किया विद्युत

संविदा कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश सिंह भोले ने बताया कि यूपीपीसीएल प्रबंधन द्वारा जिन निर्दोष संविदा कर्मचारियों को पिछली हड़ताल में बर्खास्त किया गया उनकी वापसी के लिए चेयरमैन यूपीपीसीएल आशीष कुमार

गोयल से बात चल रही है और उन्होंने महासंघ को आश्वासन दिया है कि जल्द ही समस्या का समाधान कर लिया जाएगा महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि बिजली संविदा कर्मचारी कम्प्यूटर ऑपरेटर, लाइनमैन, हेल्पर का वेतन 25 हजार करने संबंधित

वार्ता भी चेयरमैन यूपीपीसीएल आशीष कुमार गोयल से महासंघ द्वारा की जा रही है जिसपर यूपीपीसीएल प्रबंधन ने यह माना है कि जो वर्तमान समय में 11 हजार रुपये प्रतिमाह संविदा कर्मचारियों को मिल रही है वो कम है जल्द शासन स्तर पर बातचीत कर वेतन बढ़ोतरी की जाएगी महासंघ के उपाध्यक्ष दिनेश सिंह भोले ने बताया कि बिजली संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह हाउस व बिजली एलाउंस की माँग भी यूपीपीसीएल प्रबंधन से की गई है जबकि मुआवजे की माँग को यूपीपीसीएल प्रबंधन ने स्वीकार करते हुए मुआवजा धनराशि 10 लाख रुपये दुर्घटना मुआवजा घोषित किया है।

छठ पूजा के प्रांतीयकरण की याचिका को सदन में उठाया



बीपीएस न्यूज

कानपुर। विधायक सुरेन्द्र मैथानी ने एक महत्वपूर्ण कदम

उठाया, जिसके अंतर्गत, छठ पूजा के आयोजन को प्रांतीयकरण में शामिल करने की याचिका को

स्वीकृति मिली। यह याचिका विधायक सुरेन्द्र मैथानी द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिसमें छठ पूजा के

महापर्व को, कानपुर में भी सरकार द्वारा, दिव्य एवं भव्य तथा नियंत्रित और संगठित तरीके से मनाने की अपील की गई थी विधायक ने बताया कि छठ पूजा, जो कि उत्तर प्रदेश सहित देशभर में बड़े श्रद्धा और धूमधाम से मनाई जाती है, विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी भारत में इसका अत्यधिक महत्व, और करोड़ों भक्त हैं और मुख्य रूप से, हर वर्ष लाखों श्रद्धालु भक्तगण, छठी मईया के पूजन के लिए, घाटों पर पहुंचते हैं और इस महापर्व को बड़े उत्साह के साथ, हम सब मनाते हैं मेरी विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी छठी मैया का आयोजन होता है। यह न केवल श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बढ़ाएगा, बल्कि आयोजन के लिए आवश्यक संसाधनों का प्रबंधन भी बेहतर तरीके से किया जा सकेगा विधायक ने कहा कि, मेरा प्रयास होगा कि, मेरी इस याचिका पर, सकारात्मक निर्णय हो, जिससे कानपुर नगर के लाखों श्रद्धालुओं और छठ पूजा समितियों के लिए एक बड़ी खुश खबरी होगी।

19 ग्राम पंचायतों में 1.31 करोड़ का चारा घोटाला, सचिवों को जारी किया गया नोटिस, अफसरों ने दबा दी फाइल

♦ घाटमपुर ब्लाक में 11.67 लाख रुपए का घोटाला हुआ, स्कूटी से भूसा ढोने में 69,945 रुपए खर्च

बीपीएस न्यूज

कानपुर। चारा घोटाले में बिहार में सरकारें गिरने के बाद भी सरकारी अमले को चैन नहीं पड़ी। कानपुर नगर की स्थिति बिधनू, भीतरगांव, बिल्हौर, शिवराजपुर, सरसौल, घाटमपुर, पतारा और ककवन ब्लाक में गो आश्रय स्थलों में चारा खरीद के नाम पर सचिवों ने जमकर बंदरबांट की।

जिन 19 ग्राम पंचायतों का नाम है उनमें प्रमुख रूप से कठारा, सजेती, महिपालपुर, बौसर सरसौल, गागपुर बिल्हौर, पतारा, कटरी घाटमपुर, बेहटा गंभीरपुर, गढ़ी बिहारीपुर, खेरसा बिधनू, पलिया बुजुर्ग, सुघरदेवा, शिवराजपुर, बिल्हौर, मोहिदीनपुर, टिकवा और निवादा उधौ में चारा घोटाला सामने आया था।

चारा घोटाले में 1.31 करोड़ की कीमत दर्शाई गई है। 19 ग्राम पंचायतों में 121 किंटल भूसा स्कूटी, बाइक, कार और ऑटो से ढोया गया सोशल ऑडिट टीम ने ऑनलाइन चेक किया तो हकीकत सामने आई। चारा घोटाले की जांच पशु पालन विभाग के अधिकारी 2 साल से दबाए बैठे थे। गोशालाओं में वर्ष 2019 से 2021 के बीच खर्च रुपए का प्रशासन ने एक सप्ताह में बिल बाउंडर जमा करने के निर्देश दिए हैं। जांच में सामने आया कि

करीब 42 लाख रुपए का भुगतान गो-सेवकों के नाम पर किया गया। इसके साथ बिधनू ब्लाक के कठारा ग्राम पंचायत में 33.53 लाख रुपए का भूसा, चूनी, चोकर व चरी खरीद के नाम पर किया गया। यही नहीं बिना किसी काम के 1.60 लाख रुपए प्रधान और सचिव मिलकर डकार गए। भूसे के भंडार के लिए धर्मकांटे की फर्जी रसीद लगाकर मेसर्स श्रीसिंह ट्रेडिंग कंपनी को 4.90 लाख रुपए भुगतान दिखा गया। टिकवापुर के गोआश्रय में 3.36 लाख रुपए का गबन किया गया। इसी तरह सजेती में 80 हजार रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ। ऑडिट टीम की जांच में 19 गो-आश्रय स्थलों में फर्जीवाड़ा सामने आया। स्कूटी पर एक बार में लादकर 121 कुंतल भूसा सरसौल के रामपुर के गोआश्रय स्थल पहुंचा दिया गया था। इसमें करीब 69,945 रुपए खर्च होना भी बताया। धर्मकांटे में भूसा तौल कराने की कंप्यूटराइज्ड रसीदें भी लगाई थीं। ऑडिट टीम ने बिल में दर्ज नंबर को जब परिवहन विभाग के एप पर चेक किया तो पता चला कि किसी ट्रैक्टर या लोडर का नहीं बल्कि वह स्कूटी का निकला। ऑडिट टीम ने गो-आश्रय स्थलों की जांच कर सितंबर 2022 में अपनी रिपोर्ट तत्कालीन डीडीओ और तत्कालीन मुख्य

पशु चिकित्साधिकारी आरपी मिश्रा को सौंपी थी। तत्कालीन सीडीओ महेंद्र कुमार ने जांच कराकर कार्रवाई के आदेश दिए थे। लेकिन, अफसरों ने सचिव और प्रधानों की मिलीभगत से जांच ही दबा दी। जिसको अफसर अभी तक दबाए बैठे रहे। ऑडिट विभाग ने मामले की जानकारी जब शासन पर दी तो शासन ने सीडीओ दीक्षा जैन को मामले में कार्रवाई कर रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने संबंधित सचिवों को पत्र लिखकर जवाब-तलब किया। ऑडिट टीम ने घाटमपुर की कटरी ग्राम पंचायत में भी गोआश्रय स्थल तक भूसा पहुंचाने का फर्जी बिल पकड़ा। गोशाला में भूसे के आने और धर्मकांटा पर उसके तौले जाने की रसीद की डेट में करीब 10 महीने का अंतर पकड़ा। रिपोर्ट के अनुसार ओम धर्मकांटा हिलौली रोड उन्नाव की रसीद में 7 नवंबर 2019 को भूसा तौला गया था जबकि गो आश्रय स्थल के स्टॉक रजिस्टर में यह 14 सितंबर 2020 को आया दिखाया गया था। मामले में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी आईडीएन चतुर्वेदी ने बताया कि ऑडिट टीम की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई उसके आधार पर सचिवों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में बिल मांगे गए हैं।

तीन दिवसीय वार्षिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ

कानपुर। सीएसए के अधीन संचालित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में तीन दिवसीय वार्षिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ बैंक ऑफ बड़ौदा, मुख्य शाखा के सहयोग से डॉक्टर एन के शर्मा, अधिष्ठाता की अध्यक्षता में महाविद्यालय के खेल मैदान में प्रारंभ किया गया। इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन सत्येंद्र पाल, निदेशक, शारीरिक शिक्षा द्वारा किया गया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए सुरेंद्र सिंह, रोजनल मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं विशिष्ट अतिथि अजय दुबे, प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा, पंचायती राज महाविद्यालय का स्वागत डॉक्टर एन के शर्मा, अधिष्ठाता द्वारा बुके देकर किया गया। मुख्य अतिथि के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारीगण हिमांशु पिंपल, ब्रांच मैनेजर, नवीप एवं प्रशांत मिश्रा भी उपस्थित हुए। आए हुए समस्त अतिथियों का स्वागत महाविद्यालय द्वारा बुके देकर किया गया कार्यक्रम का संचालन मनीष कुमार सहाय ने किया।

स्टूडेंट फेडरेशन ने मोहसिन की तत्काल अरेस्टिंग और मेडल वापस लेने की रखी मांग

कानपुर, 17 दिसम्बर (निस)। आईआईटी पीएचडी रिसर्च स्कॉलर यौन उत्पीड़न में फंसे एसीपी मोहसिन खान को अरेस्टिंग को लेकर अब सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं। बजरंग दल के बाद अब स्टूडेंट फेडरेशन ने मंगलवार को डीएम को ज्ञापन सौंपा है।

इसके साथ ही एसीपी को मिले सभी मेडल भी वापस लेने, गर्ल्स शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा की मांग की है। एसीएम ने ज्ञापन स्वीकार करने के साथ ही मामले का संज्ञान लेने का भरोसा दिलाया।

स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कानपुर डीएम से संबोधित मुख्यमंत्री के नाम मंगलवार को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने एसीपी मोहसिन खान की तत्काल प्रभाव से अरेस्टिंग की मांग की है। इसके साथ ही एसीपी के सिल्वर मेडल वापस लेने की मांग की गई है। इसके साथ ही ज्ञापन में मांग की है कि पुलिस महकमे से जुड़े हुए इस हाई प्रोफाइल केस की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इससे कि उसे विभाग में होने का

मोहसिन खान ने दूसरे दिन लखनऊ मुख्यालय में जाकर जाँइन किया। इसके बाद वह मेडिकल लगाकर चले गए। मोहसिन इसके बाद दोबारा वहां नहीं गए। पुलिस ने इस मामले से जुड़े कई सबूत इकट्ठा किए हैं। आईआईटी के हॉस्टल से रजिस्टर, सीसीटीवी, डीवीआर

अपने कब्जे में लिए थे। पुलिस के मुताबिक, रजिस्टर में मोहसिन खान की एंट्री है। सीसीटीवी फुटेज में भी मोहसिन खान हॉस्टल के अंदर आते-जाते दिख रहे हैं। पुलिस का कहना है कि अभी मामले की जांच चल रही है, कई और लोगों के भी बयान लिए जाएंगे।

सीपी कार्यालय में महिला का पनकी थाने में तैनात सिपाही पर लगाया गंभीर आरोप

कानपुर। पुलिस कमिश्नर ऑफिस में शुक्रवार को एक महिला कमिश्नर दफ्तर के बाहर जमीन पर बैठ गई। बोली जब तक मुझे ईसाफ नहीं मिलेगा मैं यहीं बैठूंगी। मामले को समझने एडीसीपी जिला क्राइम अमिता सिंह पहुंची तो रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ी बोली, अगर मुझे ईसाफ नहीं मिलता तो यहीं जान दे दूंगी। पनकी थाने में तैनात कॉन्स्टेबल ने शादी का झांसा देकर रेप और फिर एवॉर्शन कराया। इसके बाद शादी से मुकर गया। कॉन्स्टेबल के खिलाफ तहरीर दी तो मुकदमे से बचने को शादी करके 3 महीने अपने साथ रखा और फिर अब घर से भगा दिया। मामले का संज्ञान लेकर एडीसीपी महिला अपराध के कर्तव्य का आश्वासन दिया है।



उर्सला के आईसीयू दरवाजे पर चली गोली, स्टॉफ डरकर भागा

बीपीएस न्यूज

कानपुर। उर्सला अस्पताल में मंगलवार रात अचानक से धमाके की आवाज हुई। धमाके के बाद स्टॉफ पहुंचा, तो देखा कि आईसीयू के बाहर जाने के गेट में गोली का निशान है। एक बुलेट नर्सिंग स्टेशन के पास पड़ी है। इसके बाद अस्पताल में अफरातफरी मच गई। आनन फानन में पूरा स्टॉफ आईसीयू के बाहर आ गया। पुलिस जांच कर रही है। उर्सला अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. एचडी अग्रवाल ने बताया कि रात करीब 1.15 बजे आईसीयू में बहुत तेज धमाका सा हुआ। इसके बाद लोग आईसीयू के स्टॉफ ने जांच पड़ताल शुरू की तो देखा कि गेट में एक छेद है जब और जांच पड़ताल शुरू की तो स्टॉफ को मौके से बुलेट भी पड़ी मिली। इसके बाद तत्काल घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर आकर जांच पड़ताल की है। उर्सला अस्पताल के परिसर में कई ऐसे मकान हैं, जिसमें अनाधिकृत रूप से स्टॉफ के कुछ लोग रह रहे हैं। रिटायरमेंट होने के बाद भी बहुत से कर्मचारियों ने कब्जा कर रखा है। ये लोग आए दिन अस्पताल में किसी न किसी रूप से स्टॉफ को परेशान करते हैं। इन लोगों पर प्रशासन की भी निगाह नहीं पड़ती है। आखिर गोली कहाँ से चली और किसने चलाई ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। कोतवाली एसीपी आशुतोष शुक्ला ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।



बीपीएस न्यूज

कानपुर। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में जनपद में चल रहे विकास कार्यों एवं एक करोड़ से ऊपर की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान जनपद में स्पेशल टास्क

फोर्स कार्यालय भवन का निर्माण, अग्निशमन केंद्र, पनकी के प्रशासनिक भवन, हृदय रोग संस्थान में जी+3 भवन का निर्माण, आईटी0आई0 कल्याणपुर एवं पांडुनगर में निर्माणधीन आईटी0टी0 लैब, 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय, जयपुरिया के निकट पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु, दादा नगर के पास निर्मित रेल

उपरिगामी सेतु के समानान्तर दूसरे 2 लेन रेल उपरिगामी सेतु निर्माण, मेडिकल कालेज कानपुर के प्रथम चरण के अन्तर्गत अति आवश्यक प्राथमिकता के विद्युत सुरक्षा से संबंधित निर्माण कार्यों आदि की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा उपर्युक्त

योजनाओं से संबंधित उपस्थित संबंधित अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश दिए गए अधिशाषी अभियंता आवास विकास परिषद निर्माण खंड-1 तथा नगर निगम से बिना पूर्व सूचना अनुसंधित रहने के कारण दोनों संबंधित अधिकारियों का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को दिए गए।

जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि निर्माण कार्य की बैठकों में कार्यदायी संस्थाओं के साथ-साथ परियोजना से संबंधित विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे साथ ही विभागाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर स्वयं निर्माण का निरीक्षण कर कमियों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में निर्माणधीन जयपुरिया के निकट पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु एवं दादा नगर के पास निर्मित रेल उपरिगामी सेतु के समानान्तर दूसरे 2 लेन रेल उपरिगामी सेतु निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर गुणवत्ता की जांच करना सुनिश्चित करें। कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 के द्वारा निर्माणधीन कार्यों की धीमी प्रगति होने के दृष्टिगत कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 को चेतावनी निर्गत किए जाने के निर्देश जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को निर्देश दिए गए। मेडिकल कालेज कानपुर के प्रथम चरण के अन्तर्गत अति आवश्यक प्राथमिकता के कराए

जाने वाले विद्युत सुरक्षा के कार्य की क्रास जांच कराने के निर्देश अधिशाषी अभियंता केस्को को दिए साथ ही राजकीय मेडिकल कालेज कानपुर से संबद्ध लाला लाजपत राय चिकित्सालय, कानपुर में कराए जाने वाले अग्निशमन सुरक्षा के कार्य की क्रास जांच जिला अग्निशमन अधिकारी से कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि कार्यदायी संस्था के संबंधित नोडल अधिकारी जिले से बाहर बिना जिलाधिकारी की अनुमति के न जाए यदि बिना अनुमति के गए तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी ईशा शर्मा समेत अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

ऑपरेशन त्रिनेत्र पर ग्राम प्रधानों की एक दिवसीय कार्यशाला

बीपीएस न्यूज

कानपुर। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा सुदृढीकरण और प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी द्वारा बुधवार को कैलाश भवन, सीएसए में ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राम प्रधानों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के प्रति जागरूकता बढ़ाने व ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाने, ग्रामीण क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाने, ग्राम सुरक्षा समितियों के प्रभावी क्रियान्वन सहित सुरक्षा के सुदृढीकरण सम्बन्धी अन्य विभिन्न विषय रहे।

इस दौरान कामिश्नरेंट पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत किए जा रहे विशेष प्रयासों की भी जानकारी दी गई। कानपुर नगर क्षेत्र के विभिन्न ग्राम प्रधानों व व्यापारियों द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र के अन्तर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गये हैं। पुलिस आयुक्त अखिल कुमार द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र के अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की गई। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त अखिल कुमार, जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन, जिला पंचायत राज अधिकारी, सहायक पुलिस आयुक्त/नोडल अधिकारी ऑपरेशन त्रिनेत्र, बी0डी0ओ0, ग्रामीण क्षेत्रों के थाना प्रभारी, समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव आदि उपस्थित रहे।

बीआईएस टीम ने दो सर्राफा कारोबारियों पर छापेमारी

बीपीएस न्यूज

कानपुर। बुधवार को लखनऊ से आई बीआईएस टीम ने बिरहाना रोड में दो सर्राफा कारोबारियों पर छापेमारी की। बिरहाना रोड स्थित धोबी मोहाल में रवि एंड संस और चौक सर्राफा स्थित कमलेश सिंह एंड संस के प्रतिष्ठान पर छापेमारी की। छापेमारी से पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। हालांकि 5 घंटे जांच के बाद टीम लखनऊ रवाना हो गई। सूत्रों के मुताबिक भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) टीम को कोराबारियों के यहां से सोने के आभूषणों में नकली हॉलमार्क लगाने की शिकायत की गई थी। जिसके बाद लखनऊ से आई टीमों ने छापेमारी की। टीम ने बीआईएस अधिनियम और हॉलमार्किंग विनियमों का उल्लंघन बताते हुए जांच की। बीआईएस टीम ने सर्राफा कारोबारियों के पर छापेमारी के दौरान खरीदारी और दिए जाने वाले बिल की भी जांच की। छापेमारी के दौरान पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। छापेमारी के दौरान किसी भी कर्मचारी को संस्थान से बाहर नहीं जाने दिया गया। वहीं ग्राहकों को भी बाहर कर दिया गया।

पुलिस ने तमंचा समेत अभियुक्त को धर दबोचा



बीपीएस न्यूज

कानपुर। पुलिस आयुक्त कामिश्नरेंट कानपुर नगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त पश्चिम कामिश्नरेंट कानपुर नगर अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिम कामिश्नरेंट कानपुर नगर

व सहायक पुलिस आयुक्त कल्याणपुर कामिश्नरेंट कानपुर नगर के कुशल नेतृत्व व मार्ग दर्शन में प्रभारी निरीक्षक कल्याणपुर द्वारा गठित टीम ने दौरान चैकिंग अभियुक्त बोरु चन्देल पुत्र बच्चू सिंह नसीब अली चौराहा नानकारी आईआईटी एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के बारासिरोही नहर से

लगभग 100 मीटर आगे लोथर रोड की तरफ उक्त व्यक्ति को नहर पटरी पर खम्भे के पास पकड़ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कल्याणपुर पर मु0अ0सं0 576/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही की गई। अभियुक्त वीरु चन्देल पुत्र बच्चू सिंह नसीब अली चौराहा नानकारी आईआईटी, आपराधिक इतिहास मु0अ0सं0 576/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना कल्याणपुर, बरामदगी विवरण-एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर गिरफ्तार करने वाली टीम नि0 अमित कुमार सहाय चौकी प्रभारी, उ0नि0 सौरभ सिंह रोहित कुमार थाना कल्याणपुर रहे।

अखिल भारतीय अल्पसंख्यक महासभा द्वारा विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस



बीपीएस न्यूज

कानपुर। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार अखिल भारतीय अल्पसंख्यक महासभा द्वारा विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर कुली बाजार स्थित संस्था के कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के उपाध्यक्ष कारी आरिफ रजा कादरी ने की मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय सचिव सरदार राजेंद्र सिंह नीटा शामिल हुए मीटिंग को संबोधित करते हुए महामंत्री महबूब आलम खान ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी संस्था द्वारा विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया संगोष्ठी के माध्यम से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने-

अपने विचार रखे गए जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे महामंत्री महबूब आलम खान ने कहा कि दुनिया भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया जाता है ज्ञात हो की सन 1992 में इसी दिन संयुक्त राष्ट्र ने अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों से जुड़ी घोषणा को अपनाया था इस दिन को मनाने का मकसद अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है ताकि अल्पसंख्यक समुदाय अपने अधिकारों को समझ सके लेकिन विडंबना देखिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर ना तो सरकार और ना कोई संस्थान बात करना चाहता है देश

में अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं लगभग खाना पूरी तक ही सीमित रह गई है हमारे शहर कानपुर में वकफ की संपत्तियों पर धड़ाधड़ कब्जे हो रहे हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं कब्रिस्तानों पर लगातार अतिक्रमण बढ़ते जा रहे हैं अल्पसंख्यक विभाग भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरीके से नहीं निभा रहा जिससे भूमाफियाओं के हौसेले बुलंद हम केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार से यह मांग करते हैं कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हुए जो वादे किए गए थे उनको अमली जामा पहनाया जाए साथ ही अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं

का शेष बजट जारी किया जाए देश भर में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाए तभी आप द्वारा दिया गया नारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नारी का सपना साकार होगा राष्ट्रीय सचिव सरदार राजेंद्र सिंह नीटा ने कहा कि हमें केंद्र सरकार व राज्य सरकार से उम्मीद है कि आने वाले नव वर्ष में अल्पसंख्यकों के

अधिकारों की रक्षा एवं उत्थान की योजनाओं पर ध्यान देते हुए काम किया जाएगा ताकि हम अल्पसंख्यक भी समाज की मुख्य धारा से जुड़कर महान लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत में जीवन यापन कर सकें गोष्ठी को विभिन्न वक्ताओं ने संबोधित किया मुख्य रूप से महामंत्री महबूब आलम खान उपाध्यक्ष करी आरिफ रजा कादरी राष्ट्रीय सचिव सरदार

राजेंद्र सिंह नीटा संयुक्त सचिव महताब आलम अंसारी उपाध्यक्ष पादरी डायमंड युसुफ फैज उन नबी सचिन असद सिद्दीकी इम्तियाज मदनी पाषंद उमर मंसूरी मोहम्मद हनीफ गंधी मनोज सोलोमन सरदार सहज प्रीत सिंह गोविंद शारिक सिद्दीकी मोहम्मद उस्मान मोहम्मद आजम नावेद खान आदि मौजूद रहे

डिजिटल सुरक्षा पर ओपीएफ में सेमिनार का आयोजन

बीपीएस न्यूज

कानपुर। ग्लाइडर्स इण्डिया लिमिटेड (जीआईएल) की इकाई आयुध पैराशूट निर्माणी (ओपीएफ) में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की ओर से साइबर अपराध एवं डिजिटल सुरक्षा विषय पर महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान एसबीआई कानपुर मुख्य शाखा के एजीएम संजय हैदर ने नेतृत्व में आई टीम के विशेषज्ञ अधिकारियों ने साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के विभिन्न पहलुओं की जानकारी साझा किये। ओपीएफ के मुख्य सभागार

में आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुये महाप्रबंधक एमसी बालासुब्रमणियम ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने टेक्नोलाजी के इस युग में बड़ी साधना की के साथ अपने वित्तीय व्यवहार, डिजिटल बैंकिंग और अन्य आनलाइन कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया। एसबीआई के एजीएम संजय हैदर ने कहा कि आज के दौर में हर रोज साइबर फ्राड्स, फिशिंग, डिजिटल पेमेंट आण्णस में धोखाधड़ी तथा कार्ड फ्राड्स आदि हो रहे हैं, इससे बचने के लिए धैर्य के साथ बैंकिंग

व्यवहार किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा मेहनत से कमाये हुये पैसे को लुटने वाले आपके दायें-बायें घूम रहे हैं। उन्होंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा साइबर अपराधों से बचने के सूत्र भी साझा किये एसबीआई की विशेषज्ञ अधिकारियों की टीम में प्रभात अवस्थी, अमित कुमार, शोभना शर्मा, ऋषिका बस्सी, गौतम एस. दवास, आशीष राजपूत, विनीत तथा संदीप कुमार सिंह आदि शामिल रहे। टीम के सदस्यों ने साइबर क्राइम के विभिन्न पहलुओं पर विचार रखे। प्रज्नेशन के द्वारा साइबर जालसाजों से बचने के तरीकों के बारे में भी जानकारी प्रदान की।

विविध में ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम का शुभारंभ

बीपीएस न्यूज

कानपुर। कुलपति के मार्गदर्शन में बुधवार को स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट विभाग द्वारा ओपन एण्ड डिस्टेंस लर्निंग (ओ.डी.एल./ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम का मैनेजमेंट और कॉमर्स (बीबीए, एम बी ए, बी. कॉम और एम. कॉम) के छात्रों के लिए शिक्षारम्भ कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुधांशु पांड्या, डीन व डायरेक्टर, स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट ने छात्रों को बताया कि कैसे ऑनलाइन माध्यम से हम अपनी शिक्षा को बेहतर बना सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रो. अंशु यादव, डीन ऑफ प्रोजेक्ट ने छात्र-छात्राओं का उत्साह वर्धन करते हुए असफलताओं से पार पाने की योजना बताया और प्रो. संदीप कुमार सिंह, डायरेक्टर, सेंटर ऑफ डिस्टेंस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम ने छात्रों को ओडीएल के बारे में विस्तृत जानकारी दी। डॉ.

अंशु सिंह, असिस्टेंट डायरेक्टर, सेंटर ऑफ डिस्टेंस ऑनलाइन लर्निंग ने डी-कोड की कार्यकरिणी के सदस्य के बारे में बताया। वहीं, श्रीमती सोमन गुप्ता ने पीपीटी के माध्यम से ओडीएल/ओ एल स्टडी प्रक्रिया को छात्रों को समझाया इस कार्यक्रम का संचालन श्रीमती पञ्चवी मिश्रा और श्रीमती मानसी बाजपेई ने किया। कार्यक्रम का समन्वय डॉ. चारु खान और डॉ. अर्पणा कटियार द्वारा किया गया इस ऑनलाइन ऑरिएंटेशन प्रोग्राम में डी-कोड की कार्यकरिणी के सदस्य, डिप्टी डायरेक्टर (टेक्निकल) प्रोफेसर आशीष कुमार श्रीवास्तव, लाइब्रेरियन और असिस्टेंट डायरेक्टर, डॉ. संजीव कुमार सिंह, और टेक्निकल मैनेजर इंजीनियर सोमेश कुमार मल्होत्रा, साथ ही सभी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मनोज कुमार, पी.एन. पांडे, राहुल अग्रवाल, और अन्य विभाग के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉ. पूजा सिंह तथा अन्य ने भी भाग लिया।

कुत्तों हेतु निशुल्क टीकाकरण एवं हेल्थ चेकअप कैम्प का आयोजन

बीपीएस न्यूज

कानपुर नगर निगम कानपुर के द्वारा प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक मोतीझील स्थित प्रमिला सभागार में कुत्तों हेतु निशुल्क टीकाकरण एवं हेल्थ चेकअप कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें टीकाकरण के लिये प्रमिला सभागार में आने वाले श्वानों को निशुल्क वैक्सीन के साथ-साथ निशुल्क डॉग मैट्रेस व रेडियम डॉग कॉन्टर भी प्रदान किया जायेगा। इसके अलावा ऑन स्पॉट डॉग रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन ऑन लाइन एवं ऑफ लाइन दोनो माध्यमो से कराया जा सकता है। ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन हेतु ज़ंदचनत बबि लच पर ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं तथा ऑफ लाइन रजिस्ट्रेशन हेतु नगर निगम कानपुर के मोतीझील मुख्यालय स्थित कैटिल कैचिंग विभाग से सम्पर्क करें। पालतू कुत्तों का लाइसेंस शुल्क प्रति कुत्ता विदेशी

नस्ल रू0 500.00 एवं देशी नस्ल रू0 200.00 है। ऐसे श्वान मालिक जिन्होंने पूर्व में अपने श्वान का लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन कराया था परन्तु अभी तक उसका नवीनीकरण नहीं कराया है वो भी अपने श्वान के लाइसेंस को नवीनीकरण करा सकते हैं। नगर निगम कानपुर सीमान्तगत बिना लाइसेंस के पाले जा रहे पालतू कुत्तों के मालिकों के विरुद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही की जायेगी जिसमें पेनाल्टी/जुर्माना एवं कुत्तों को जब्त किये जाने का प्राविधान है। अतः शीघ्र ही अपने पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें जिससे अनावश्यक असुविधा से बचा जा सके। कैम्प में प्रतिभाग करने वाले श्वान मालिकों को विभिन्न निशुल्क सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने-अपने श्वानों को कैम्प में लाना अनिवार्य है। अतः समस्त श्वान/पशु प्रेमियों से आग्रह है कि आगामी कैम्प का लाभ उठाये।

बीपीएस न्यूज

कानपुर। अस्पताल कर्मचारियों के बीच मेनोपॉज के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए, कानपुर मेनोपॉज सोसाइटी (केएमएस) और प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर के द्वारा एक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय मेनोपॉज सोसाइटी की जन जागरूकता समिति के तत्वावधान में यह कार्यक्रम ओल्ड सिम्पसा हॉल में किया गया।

डॉ.मीरा अग्निहोत्री ने मेनोपॉज वेलनेस सिम्पोजियम का उद्देश्य जीवन के इस महत्वपूर्ण चरण में महिलाओं के लिए रोकथाम एवं

उपचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए मेनोपॉज से संबंधित महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों पर मूल्यान जानकारी देना बताया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉ. किरण पांडे ने ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम रणनीतियों और उपचार विकल्पों पर चर्चा की, जो रजोनिवृत्ति के दौरान और बाद में महिलाओं को प्रभावित करती है। इसी क्रम में डॉ. रेनु गुप्ता प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर ने असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव के विषय पर संबोधित किया, जो एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्भाशय के कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, और उससे सम्बन्धित नवीनतम

उपचार पर प्रकाश डाला। जागरूकता पहल के हिस्से के रूप में सभी 65 प्रतिभागियों का चेकअप किया गया तथा निःशुल्क होमोग्लोबिन और बीएमडी परीक्षण कराया गया। साथ ही सभी को फल व दूध के पैकेट्स का वितरण भी किया गया। डॉ. शैली अग्रवाल सचिव, कानपुर मेनोपॉज सोसाइटी ने बताया कि यह कार्यक्रम स्वास्थ्य कर्मियों के बीच मेनोपॉज के बारे में गहरी समझ को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है कि महिलाओं को उनके जीवन के इस महत्वपूर्ण चरण के दौरान सर्वोत्तम संभव देखभाल मिले कार्यक्रम को मुख्य संचालक डॉ. दिव्या द्विवेदी ने कार्यक्रम का



संचालन किया। इस दौरान मुख्य रूप से डॉ. नीना गुप्ता, डॉ. सीमा द्विवेदी, डॉ. वंदना शर्मा, डॉ. पविता

लाल, डॉ. गरिमा गुप्ता, डॉ. प्रतिमा वर्मा, डॉ. अनीता गौतम एवं अन्य सकाय सदस्य मौजूद रहे।

संभल के बाद अब बेकनगंज और चमनगंज के मंदिर खंगाले गए

- एनजीओ और पुलिस फोर्स ने तीन मंदिरों से कब्जे हटवाये
- मूर्तियां खंडित और गंदगी मिली, अब शुरू होगा पूजा-पाठ
- चमनगंज, बेकनगंज में 125 से ज्यादा मंदिरों पर कब्जा
- कहीं मंदिर में खुली टेलर की दुकान तो कहीं बिजली चोरी में धरे गए माफिया का कब्जा

बीपीएस न्यूज

कानपुर। संभल में भारी बिजली चोरी पकड़ने के दौरान पुलिस प्रशासन ने दशकों से कब्जा करके बंद कर, अतिक्रमण में दबा दिया गया मंदिर खुलवाया। वहां पूजा पाठ भी शुरू करवाया। पर अब कानपुर महानगर के चमनगंज और बेकनगंज जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में तिरस्कृत पड़े मंदिरों की बारी है। गुरुवार को कानपुर के घनी आबादी वाले मुस्लिम क्षेत्र में स्थित तीन मंदिर से कब्जा हटाए गए। यहां सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति के पदाधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। एक शिव मंदिर और दो हनुमानजी के मंदिर

बताए जा रहे हैं। हीरामनका पुरवा के तिरपाल वाले मैदान और यहीं के जुगियाना में कुछ अन्य मंदिरों को जल्द माफियाओं के कब्जे से मुक्त करवाया जाएगा। यहां कहीं मंदिर में टेलर की दुकान खुली है, तो कहीं बिजली चोरी में धरे गए माफिया का कब्जा है।

यह सभी मंदिर हीरामनका पुरवा पंचबाग में करीब 200 मीटर की दूरी में हैं। दशकों से कब्जा करके बंद कर दिए गए थे। अब इन मंदिरों में पूजा-पाठ शुरू कराया जाएगा। वहीं सूत्रों के अनुसार बेकनगंज थानाक्षेत्र के हीरामनका पुरवा के तिरपाल वाला मैदान के अंदर और जुगियाना के बाहर तीन और भी अति प्राचीन



शिव मंदिर हैं। जिनमें से एक को भूमाफियों ने शिवलिंग और हनुमान प्रतिमा खंडित करके, चबूतरा तोड़कर, कब्जा कर लिया है। वहीं बाहर एक दूसरे मंदिर में तो न्यूटी नाम के शांतिर ने मंदिर पर कब्जा करके करिश्मा टेलर नाम से दुकान खोल रखी है। बताया गया कि न्यूटी नाम के इस शांतिर ने मंदिर की छत और दीवारों पर से सारी मूर्तियां तोड़कर उनको अपनी दुकान के फर्श पर लगा रखा है। अब सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति ब्यूटी से और तिरपाल वाला मैदान के अंदर वाले मंदिर को छुड़ाएगी।

बेकनगंज के हीरामनका पुरवा में मंदिर कब्जाने वालों में श्रीरफ भिश्ती, न्यूटी, कलीम आदि उन माफियाओं के नाम आ रहे हैं, जो हाल में ही उपचुनाव के दौरान बिजली विभाग के छापाओं में सैकड़ों कटिया लगाकर बिजली चोरी करते और समानांतर केस्को चलाते मिले थे। अकेले तिरपाल वाले मैदान में ही पीसी एक्ट के अंतर्गत 10 एफआईआर केस्को विजलेंस ने दर्ज की थीं।

गुरुवार को सुबह से हीरामनका पुरवा में मंदिरों की साफ-सफाई के दौरान यहां पुलिस बल तैनात रहा। दरअसल, हिंदू संगठन का

दावा है कि कानपुर में 125 से ज्यादा मंदिरों पर कब्जा हो गया है। उन्हें कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति के जिलाध्यक्ष उमेश तिवारी उर्फ डब्बू बाबा ने कहा, शहर के मुस्लिम क्षेत्रों में सैकड़ों मंदिरों पर कब्जा करके दुकानें खोल दी गई हैं। मंदिरों को पूरी तरह से खंडित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी उसके अवशेष हैं। इसी क्रम में हीरामन का पुरवा पंचबाग के शंकर जी का मंदिर और दो हनुमान मंदिरों को कब्जामुक्त कराया गया है। इस मामले में बेकनगंज थाने से लेकर पुलिस कमिश्नर, डीएम को लेटर लिखा था। जांच में यह सही पाया गया कि मंदिरों पर कब्जा कर लिया गया है।

इसके बाद संगठन के पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी, उपाध्यक्ष सुधीर चंद्र द्विवेदी, महामंत्री प्रेम कुमार दीक्षित उर्फ गोपाल, कोषाध्यक्ष हरी कृष्ण शुक्ला और रवि शंकर तिवारी समेत कई लोग गुरुवार को

मंदिरों पर पहुंचे पुलिस की मौजूदगी में संगठन के पदाधिकारियों ने मंदिर की साफ-सफाई की। पुलिस ने दल-बल के साथ मंदिरों पर कब्जा करके बनाई गई दुकानों को खाली कराया। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि मंदिर की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है। मंदिर पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। जल्द ही मंदिरों का मंटीनेंस, मूर्ति स्थापना और पूजा-पाठ शुरू कराया जाएगा। जिलाध्यक्ष उमेश तिवारी ने बताया कि मुस्लिम आबादी वाले केडीए के जोन-1 में आरटीआई की सूचना के मुताबिक 325 से ज्यादा मंदिर हैं। इसमें से 125 से ज्यादा मंदिरों पर कब्जा हो चुका है। संगठन ने कड़ी मशकत से कब्जा हो चुके 35 मंदिरों को तलाश कर दिया है। यह मंदिर पूरी तरह से अपना अस्तित्व खो चुके हैं। इन पर गंदगी का अंबार और मूर्तियां खंडित हैं। अधिकांश हनुमान और शिव मंदिर हैं। जल्द ही इन सभी मंदिरों को कब्जामुक्त कराया जाएगा।

सनातन रक्षा यात्रा 2.0 के समर्थन में उमड़ा जन सैलाब

◆ रक्षा यात्रा के जरिए भारतीय विरासत और मूल्यों की रक्षा का आह्वान



बीपीएस न्यूज

कानपुर। सनातन सांस्कृतिक संघ द्वारा झांसी से सनातन रक्षा यात्रा 2.0 का शुभारंभ किया गया, जिसे सनातनी भाइयों एवं बहनों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर अपना अभूतपूर्व समर्थन दिया। सनातन सांस्कृतिक संघ की अध्यक्ष हरिप्रिया भार्गव के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस जन आंदोलन का उद्देश्य भारत के सामने खड़ी सांस्कृतिक और धार्मिक चुनौतियों से निपटने के लिए समस्त सनातनियों को एकजुट करना है। यात्रा आज कानपुर पहुंची और लखनऊ के लिए रवाना होगी।

रक्षा यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर मौजूद पत्रकारों से बात करते हुए हरिप्रिया भार्गव ने बताया, यह रक्षा यात्रा में कम से कम ढाई तीन हजार लोग शामिल हैं। हम लगभग 50 बसों और 50

गाड़ियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ बाइक पर भी लोग चल रहे हैं। सब लोग मिलकर एक साथ इस यात्रा को इस उद्देश्य के साथ निकाल रहे हैं कि बांग्लादेश में सनातनी भाई बहनों के साथ जो नरसंहार हो रहा है, वहाँ के सनातनी मंदिरों, जिनालय, गुरुद्वारों का जो विध्वंस किया जा रहा है, गो माता की जो हत्या हो रही है, वो भी खुले आम, इस सबके खिलाफ हम सबको मिलकर आवाज उठानी है, और यही आवाज सरकार तक पहुँचाने के लिए हम यह रक्षा यात्रा निकाल रहे हैं। हम अपनी बात गवर्नर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति तक पहुँचाना चाहते हैं, ताकि सरकार इस दिशा में कड़े कदम उठाए। यात्रा के अगले कार्यक्रम के बारे में हरिप्रिया भार्गव ने बताया कि यह रक्षा यात्रा झांसी से

निकलकर उरई होते हुए कानपुर पहुंची। उसके अगले दिन यात्रा को गंगा आरती और पूजन के बाद लखनऊ की ओर ले जाया जाएगा। वहाँ जाकर महामहिम को अपना प्रस्ताव सौंपा जाएगा, जापन दिया जाएगा, फिर यह यात्रा अयोध्या की ओर प्रस्थान कर जाएगी। अयोध्या में सभी लोगों के लिए सामूहिक मंत्रोच्चारण और पूजा पाठ के साथ रामलला के दर्शन की व्यवस्था की गई है। हरिप्रिया भार्गव ने कहा कि हमारी श्रद्धा है कि जब हम लोग मिलकर पूरे भक्तिभाव से प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित रूप से बांग्लादेश में हो रहा नरसंहार रुकेगा और सभी सनातनी बहन भाइयों और गोमाता की रक्षा होगी। क्या भारत सरकार इस मामले में चिंतित नहीं है या पहल नहीं कर

रही है, पत्रकारों के इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "भारत सरकार पहले से कार्य कर रही है। वो पहल कर रहे हैं। हम सारे सनातनी भाई-बहन मिलकर अपनी ओर से पहल कर रहे हैं। अपना एक संदेश जन-जन तक पहुँचा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ें और मिलकर, एक होकर अपनी आवाज सभी लोगों एवं सरकार तक पहुँचाएं। इस रक्षा यात्रा में झांसी, ललितपुर, कानपुर, उरई और लखनऊ आदि सभी जगहों के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। रक्षा यात्रा में कई सारी गाड़ियों में कम से कम 3000 लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं।

पत्रकारों के माध्यम से सभी सनातनियों को संबोधित करते हुए हरिप्रिया भार्गव ने कहा, अभी मेरा सभी से एक ही अनुरोध है कि सभी लोग उठो, बाहर निकलो और एक साथ मिलकर चलो।

आओ हम सभी मिलकर इस यात्रा को सफल बनाएं और जो हिंदू सनातनी भाई-बहन सोए हुए हैं, उन सबसे मेरा आह्वान है कि अब सोने का वक्त नहीं है, अब जाग जाओ और अपने-अपने घरों से निकलकर सनातन की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाओ।

परिवार नियोजन मातृ शिशु स्वास्थ्य की नींव : एडी हेल्थ

□ परिवार नियोजन में बेहतर कार्य करने वालों को मिला सम्मान



बीपीएस न्यूज

कानपुर। मातृ शिशु स्वास्थ्य में परिवार नियोजन की अहम भूमिका है। इसे अपना कर मातृ शिशु मृत्यु दर और कुपोषण के स्तर को कम किया जा सकता है। यह बातें अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (एडी हेल्थ) डॉ संजू अग्रवाल ने कहीं। वह कानपुर मंडल में परिवार नियोजन

कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों और सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के सम्मान समारोह को सम्बोधित कर रहीं थी। गुरुवार को जनपद के विजय इंटरकांटिनेंटल होटल में हुये आयोजन के दौरान वर्ष 2023-24 में विश्व जनसंख्या दिवस, पुरुष नसबंदी पखवाड़ा और

खुशहाल परिवार दिवस के दौरान विभिन्न विधाओं में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले के लिए जनपद व ब्लॉक के अधिकारियों सहित सेवा प्रदाताओं और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को मण्डल स्तर पर अपर निदेशक ने प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। लगभग सभी विधाओं में कानपुर नगर प्रथम पर रहा। कार्यक्रम का

संचालन मंडलीय परिवार नियोजन प्रबंधक अर्जुन सिंह ने किया।

एडी हेल्थ ने कहा कि पहला बच्चा होने के बाद तुरंत गर्भधारण मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य एवं पोषण के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इस स्थिति से बचने के लिए दंपति को प्रेरित कर परिवार नियोजन का मनपसंद साधन उन्हें उपलब्ध करवाना चाहिए। अस्थायी साधन जैसे कंडोम, छाया, माला एन, ईमर्जेंसी पिल्स आदि को उपलब्धता सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से भी सुनिश्चित कराई जा रही है। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से त्रैमासिक अंतरा इंजेक्शन, आईयूसीडी और पीपीआईयूसीडी की सुविधा इच्छुक दंपति प्राप्त कर सकते हैं। परिवार पूरा होने पर नसबंदी का विकल्प चुना जा सकता है। इस कार्य में आशा कार्यकर्ता मददगार होती हैं। समुदाय में यह संदेश दिया जाना चाहिए कि प्रसव पश्चात महिला नसबंदी श्रेयस्कर है और महिला नसबंदी की तुलना में पुरुष नसबंदी सरल और सुरक्षित है।

नगर निगम में प्रवर्तन दल प्रभारी और पार्षदों में छिड़ी जंग

पार्षद दल के नेता की अगुवाई में महापौर और आयुक्त से की शिकायत

बीपीएस न्यूज

कानपुर। नगर निगम कानपुर में गठित प्रवर्तन दल और पार्षदों के बीच अक्सर विवाद होते रहते हैं। ताजा मामला प्रतिबंधित पॉलीथिन लेकर जा रहे ई-रिक्शा को छोड़ने को लेकर हो गया। ई-रिक्शा छोड़ने की मांग करने पहुंचे पार्षदों और प्रवर्तन दल प्रभारी रिटायर्ड कर्नल आलेक नारायण के बीच विवाद हो गया। काफी देर तक दोनों पक्षों में हंगामा होता रहा। इस दौरान पार्षदों ने विरोध जताकर नारेबाजी की और प्रकरण की लिखित में शिकायत की है।

भाजपा पार्षद दल के नेता नवीन पंडित ने बताया कि वह लोग नगर निगम परिसर के बाहर पार्षदों के साथ खडे आपस में चर्चा कर रहे थे, इसी दौरान एक ई-रिक्शा वाला आकर नारे लगा। कहा कि वह गरीब आदमी है उसका ई-रिक्शा कुछ सामान के साथ गया। निगम प्रवर्तन दल ने पकड़ लिया है और 10 हजार रूपए की मांग कर रहे हैं। बताया कि वह किराए का ई-रिक्शा चलाकर परिवार पालता हूँ। उसकी बात सुनकर वह और साथी पार्षद नीरज कुरील, आकर्ष

बाजपेई, अभिनव शुक्ला, आनंद शुक्ला, अमित गुप्ता के साथ प्रवर्तन अधिकारी से मिलने गए और ई-रिक्शा छोड़ने का आग्रह किया। इसी बीच आरोप हैं कि 20-25 लोग आकर गाली गालौज करने लगे। नगर निगम को गाली देते कहने लगे कि हमे ऐसी चोर संस्था में नौकरी नहीं करनी है। नवीन पंडित ने बताया कि पूर्व में प्रवर्तन दल के द्वारा अभद्रता की जा चुकी है। नगर आयुक्त को पत्र भेजकर समस्त पार्षदों ने मांग की है कि रिटायर्ड कर्नल आलोक नारायण और अन्य अभद्रता करने वालों की सेवाएं समाप्त की जाएं। पार्षदों ने कहा कि अगर न्याय न मिला तो वह आंदोलन करेंगे। वहीं, देर शाम मेयर कार्यालय ने भी कहा कि इस तरह से प्रकरण संज्ञान में आया है। मेयर ने भी पार्षदों की मांगों का समर्थन किया।

प्रतिबंधित पॉलीथिन के साथ ई-रिक्शा पकड़ा गया था, उसको छोड़ने के लिए अनर्गल दबाव पार्षदों के द्वारा बनाया गया। इस दौरान कहासुनी दोनों पक्षों से हुई, किसी पार्षद से कोई अभद्रता नहीं की गई है। जब कि पकड़ा गया ई-रिक्शा को जबरन छोड़ दिया गया है। पूरे प्रकरण से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया है। इस तरह से प्रवर्तन दल का काम करना मुश्किल है।

महापौर ने निःशुल्क एन्टी रैबीज वैक्सिनेशन कैम्प का किया शुभारंभ



बीपीएस न्यूज

कानपुर। नगर निगम के गुरुवार को मोतीझील स्थित प्रमिला सभागार में निःशुल्क एन्टी रैबीज वैक्सिनेशन कैम्प का आयोजन किया गया। शुभारम्भ महापौर प्रमिला पाण्डेय के द्वारा किया

गया। कैम्प में स्वान प्रेमियों को 300 डॉग मैट्रेस, 100 रेडियम कॉलर एवं 200 काउंट का वितरण किया गया।

श्वान प्रेमियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में लगभग 200 से अधिक कुत्तो

जर्मन शेफर्ड, सिद्ध, लेब्रा, पॉमेलियन, पग, बीगल एवं अन्य प्रजातियां% का रजिस्ट्रेशन किया गया तथा 230 से अधिक कुत्तो का निःशुल्क टीकाकरण किया गया। कार्यक्रम में महापौर द्वारा नगर के समस्त श्वान प्रेमियों से अपील की गयी कि अपने घरों में पालतू श्वानों का नगर निगम में पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। नव वर्ष में नगर निगम के डॉग कैचर द्वारा पार्कों एवं ऐसे चिन्हित स्थलों जहाँ पर भवन स्वामियों द्वारा पालतू स्वानों को घूमने हेतु लाया जाता है, पर अभियान चलाया जायेगा एवं जुमाने आदि की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, साथ ही साथ पशुपालको से अपील भी की गयी कि अपने गाय आदि

को सड़क पर खुला ना छोड़े। कार्यक्रम में उम्मीद एक किरण संस्थान, नवोदय फाउण्डेशन, डॉंगोटोरियम, कोको हाउस सहित अन्य संस्थाओं ने प्रतिभाग किया। इसके अतिरिक्त मयंक त्रिपाठी, रचना मिश्रा, शुभांगी, अलंकार, एकता सिंह, मासा, नीलम श्रीवास्तव, जस्सी, सरस्वती, कनिका मिश्रा, कनिका, अर्चना

त्रिपाठी, पूजा कुशवाहा, शिल्पा शुक्ला को महापौर के द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सोनाली पाल, सोनिया कुशवाहा, दिव्यांशु दीक्षित, अजय सिंह, विशाल, लावान्या श्रीवास्तव, ज्योती सिंह, अल्का कालरा, नेहा यादव, ललिता शुक्ला, रश्मी कटिया, अंशु सिंह एवं अन्य नागरिकों ने प्रतिभाग किया।

गंगा टास्क फोर्स ने गंगा स्वच्छता की दिलाई शपथ

बीपीएस न्यूज

कानपुर। भारतीय सेना की 137 सी ई टी एफ बटालियन टी ए 39 गोरखा राइफल गंगा टास्क फोर्स ने उपासना मेमोरियल मायावती हाई सेकेंडरी स्कूल सलेमपुर, ब्लॉक सरसौल कानपुर नगर में स्कूल के छात्र-छात्राओं के साथ मिलकर गंगा स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सदीप शर्मा स्कूल प्रिंसिपल और नेहरू युवा केंद्र के श्री राम शंकर तिवारी उपस्थित रहे। गंगा टास्क फोर्स के कमान अधिकारी कर्नल अरविंद प्रसाद एस और कानपुर स्थित कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अनूप कुमार ओझा के दिशा निदेश पर विगत 6 सालों से गंगा स्वच्छता अभियान, पौधा रोपण, घाटों की गश्त, जागरूकता अभियान निरंतर कर रही है। इस अवसर पर गंगा टास्क फोर्स के सुबेदार ललित मोहन ने स्कूल परिसर में उपस्थित छात्र छात्राओं को गंगा नदी की स्वच्छता के बारे में जागरूक करते हुए बताया कि गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है यह नदी हमारी पानी की जरूरत को पूरा करती है और यह भारत की सबसे पूजनीय नदी है इसलिए गंगा की स्वच्छता हम सभी की जिम्मेदारी है हमें नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हमें प्लास्टिक की थैलियां, बोटल, मूर्ति विसर्जन और अन्य सामग्री को नदियों या उसके किनारे पर नहीं फेंकना चाहिए।

जिलाधिकारी ने बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता में विजेताओं को किया सम्मानित

बीपीएस न्यूज

कानपुर। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह द्वारा सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में प्रयागराज में आयोजित राज्य स्तरीय बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जनपद की बालिकाओं को, उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ टीम का गौरव प्राप्त करने के उपलक्ष्य में जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश



लखनऊ एवं बॉक्सिंग संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित प्रदेश स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता जो 16 से 18 दिसंबर तक प्रयागराज में

आयोजित की गई थी। उक्त प्रतियोगिता में जनपद कानपुर नगर की खिलाड़ियों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए चैंपियन होने का गौरव

प्राप्त कर कानपुर का नाम रोशन किया। बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चार स्वर्ण, एक रजत तथा दो कांच पदक खिलाड़ियों ने जीते।

शहीदों के सपनों का भारत बनाओ बिजली का निजीकरण हटाओ दिवस मनाया



कानपुर। केस्को के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं अभियंताओं ने आज कार्यालय अवधि में सामान्य रूप से अपना कार्य सम्पादित किया तथा कार्यालय अवधि समाप्त होने के पश्चात बिजलीघर परेड पर एकत्रित हुए, जहाँ उन्होंने मानव श्रंखला बनाकर कैंडल लाइट जलाकर निजीकरण विरोधी प्लेकार्ड के साथ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शित किया इस अवसर पर सभा हुई जिसमें वक्ताओं ने कहा कि वर्ष 2000 में विद्युत परिषद का विघटन होने के समय तक अभियंता प्रबन्धन था और विद्युत परिषद बनने के बाद 1959 से 2000 तक 41 वर्षों में मात्र 77 करोड़ रुपये का घाटा था जो विद्युत परिषद का विघटन होने के बाद आई ए एस प्रबन्धन के रहते

एक लाख दस हजार करोड़ रुपये केवल 24 वर्ष में पहुँच गया। मजेदार बात यह है कि घाटे के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी प्रबन्धन की होती है किन्तु प्रबन्धन कर्मचारियों पर घाटा थोप कर अर्बों-खर्बों रुपये की सार्वजनिक सम्पत्ति पहले से तय कुछ निजी घरों को सौंपने जा रहा है। पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन द्वारा जारी किये गये घाटे के आँकड़े भ्रामक हैं और पूरी तरह झूठ का पुलिन्दा हैं। पावर कारपोरेशन प्रबन्धन के पीपीटी प्रेजेंटेशन में बिजली राजस्व बकाये की धनराशि 115825 करोड़ रुपये बतायी गयी है जिसमें दक्षिणांचल का 24947 करोड़ रुपये और पूर्वांचल का 40962 करोड़ रुपये सम्मिलित है। सवाल यह है कि यदि यह

राजस्व वसूल लिया जाये तो पॉवर कारपोरेशन 5825 करोड़ के मुनाफे में है फिर घाटे का झूठ फैलाकर निजीकरण करना किस साजिश का हिस्सा है। वर्ष 2010 में जब टोरेण्ट पॉवर को आगरा का फ्रेंचाइजी दिया गया था तब आगरा में राजस्व वसूली का 2200 करोड़ रुपये बकाया था। आज 14 साल गुजर जाने के बाद भी टोरेण्ट कम्पनी ने इस बकाये की धनराशि का एक रूपये भी पॉवर कारपोरेशन को नहीं दिया है। अब दक्षिणांचल और पूर्वांचल डिस्कॉम, जिन्हें बेच जा रहा है,

उनका बकाया लगभग 66000 करोड़ रुपये है। निजीकरण के बाद यह 66000 करोड़ रुपये डूब जायेगा और निजी कम्पनियों की जेब में चला जायेगा। ऐसा लगता है कि पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन इस साँठ-गाँठ का हिस्सा है। सभा में अमर शहीदों पण्डित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ल खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर शपथ ली गयी कि बिजली का निजीकरण किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे और निजीकरण का निर्णय वापस लिए जाने तक लोकतांत्रिक

ढंग से संघर्ष किया जायेगा। सभा की अध्यक्षता भगवान मिश्र ने की सभा को पी. एस. बाजपेयी, रफीक अहमद, बी. के. अवस्थी, ई. लव बंसल, विजय त्रिपाठी, असित कुमार सिंह, बालेंद्र कटियार, कपिल मुनि, राजा भरत अवस्थी, एस. ए. एम. जैदी, गौरव दीक्षित, विष्णु पांडेय, राजीव खरे, जी. एस. श्रीवास्तव, राम प्रकाश राय, उमा कान्त, आरिफ बेग, राम शंकर मिश्रा, शम्भू सिंह, राणा प्रताप, मो. वशी, हश्यत, पवन, शिव शंकर, अहमद, रणधीर सिंह, के. के. अवस्थी ने सम्बोधित किया।

अटल जी के 100वें जन्मदिन पर भाषण एवं काव्य प्रतियोगिता का आयोजन

कानपुर। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्मदिन के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाषण और काव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसका विषय अटल जी के शासन का प्रभाव और उनकी दृष्टि रहा। कार्यक्रम का संस्थान के निदेशक प्रो. सुधांशु पांड्या, प्रशासन समन्वयक डॉ. विवेक सचान, डॉ. प्रशांत त्रिवेदी, और डॉ. सिधांशु राय ने दीप प्रज्वलित किया। डॉ. प्रकाश नारायण पांडे ने अटल जी के प्रेरणादायक जीवन, उनकी काव्यात्मक प्रतिभा और उनके नेतृत्व की दूरदर्शिता पर प्रकाश डाला। भाषण प्रतियोगिता में छात्रों ने अटल जी के शासनकाल की उपलब्धियों, उनके सुशासन और काव्यात्मक दृष्टिकोण को अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। भाषण प्रतियोगिता में श्रुति दीक्षित ने प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान पर आस्था शुक्ला और तृतीय स्थान पर लीना मकड़ रहीं। काव्य प्रतियोगिता में श्रुति दीक्षित ने अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुति से प्रथम स्थान हासिल किया।

बुजुर्गों के लिए खुशख़बरी, 60 साल से ज़्यादा उम्र के सभी नागरिकों का होगा इलाज मुफ्त

दिल्ली के हमारे सभी बुजुर्गों के लिए खुशख़बरी। दिल्ली में 60 साल से ज़्यादा उम्र के सभी नागरिकों का इलाज मुफ्त होगा। ये केजरीवाल की गारंटी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बुढ़ापे में एक चीज सभी को तकलीफ देती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे 100 बीमारियाँ आदमी को आफर घेर लेती हैं। सबसे बड़ी चिंता इलाज की होती है। ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो अच्छे खासे परिवार से आते हैं। लेकिन उनके बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते हैं। बुढ़ापे में मैंने अच्छे अच्छे परिवार के मां-बाप, बुजुर्गों को तड़पते देखा है। मां-बाप को उनके बच्चों ने छोड़ दिया। लेकिन आप चिंता मत करना आपका ये बेटा अभी जिंदा है। अरविंद केजरीवाल ने

कहा कि रामायण में एक कहानी पढ़ते हैं न जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे। आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए एं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूँ। आम आदमी पार्टी की यह योजना मुख्य रूप से बुजुर्गों के स्वास्थ्य और पेंशन पर केंद्रित होगी। संजीवनी योजना के तहत बुजुर्ग पेंशन बढ़ाई जा सकती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली के कोने कोने से सम्मानित बुजुर्ग हमारे बीच आए हुए हैं। आज मैं जो घोषणा करने जा रहा हूँ वो शायद भारत के इतिहास में कभी घोषणा नहीं की गई। केजरीवाल ने कहा कि हम बुजुर्गों का बहुत मान सम्मान करते हैं और आपको

वजह से आज हम हैं। देश को आप ही लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया। 24 घंटे मेहनत करके अपने परिवार को पाला और समाज व देश को आगे बढ़ाया। अब बुढ़ापे में हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको ख्याल रखें। हमने दिल्ली में श्रवण कुमार से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा शुरू की। इस योजना के तहत अब तक एक लाख बुजुर्ग देश के कोने कोने में तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। इसमें रामेश्वर, शिर्डी, अयोध्या, वृंदावन, अजमेर शरीफ, पूरी, द्वारकाधीश काफ़ी सारे स्थान आते हैं। आप लोग वहाँ तीर्थ यात्रा करके आए सारा खर्च दिल्ली सरकार देती है। आपको आपके घर से एक बस आती है लेने के लिए। वहाँ से रेलवे स्टेशन पर एसी ट्रेन होती है और वहाँ आपको पूरी खातिर की

जाती है। रास्ते का पूरा सामान आपको एक थैले में दिया जाता है। जहाँ पहुँचते हैं वहाँ बस का इंतजाम रहता है। होटल फ्री होता है। आपका आने जाने, रहने खाने-पाने का सारा खर्च दिल्ली सरकार देती है। बदले में हमें और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को दुआएँ मिलती हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं होती है।

पिछले हफ्ते ही केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था, जिसके तहत दिल्ली की 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये जबकि चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। ये ऐलान अगले साल होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले किया गया है।

खेतों में दफन मिले लापता 'लाखों लोग, इकट्ठा की जा रही हैं खोपड़ियाँ और हड्डियाँ

सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे का बाद राष्ट्रपति पद पर बैठे असद अल बशर तो देते छोड़कर भाग गए हैं लेकिन उनके ज़रिए की गई करतूत अब खुलकर सामने आ रही हैं। पिछले हफ्ते ब्लूमन राइट्स वॉच ने दक्षिणी दमिश्क के तदामोन इलाके का दौरा किया तो किसी के भी होस उड़ाने देने वाली हकीकत सामने आ गई। दरअसल टीम को यहां मानव अवशेष मिले। बताया जा रहा है कि यहां उन लोगों लाखों

लोगों की लाशें दफन हैं जिन्हें असद के शासनकाल में यातनाएं दे देकर जना से मार दिया गया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक यब कब्रिस्तान दमिश्क के केंद्र से लगभग 10 किमी दूर उत्तर-पश्चिमी उपनगर अद्रा में मिला है। इस इलाके को सीमेंट की दीवारों से घेरा गया है। असद के सत्ता से हटने के बाद निवासियों, फोरेंसिक टीमों और अंतरराष्ट्रीय समूहों को मृतकों का पता लगाने

में एक मुश्किल और लंबी जिद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कई साल लग सकते हैं। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय, अकाउंटैबिलिटी कमिशन, सीरियाई इमरेजेंसी फोर्स समेत कई एजेंसियाँ इन कब्रों की पहचान करने के लिए गवाहों के विवरण और सेटलाइट तस्वीरें इकट्ठा कर रहे हैं। पूर्व अमेरिकी युद्ध अपराध राजदूत स्टीवन रैप मंगलावार को इस जगह पर ही थे। उनका कहना है कि अकेले साइट पर कई हजार शव दफनाए गए होंगे। पूर्व अमेरिकी राजदूत रैप, सामूहिक कब्रों को पंजीकृत करने और युद्ध अपराधों में शामिल अधिकारियों की पहचान करने में मदद करने के लिए दो संगठनों के साथ काम कर रहे हैं।

टीम अवशेषों को बाहर निकाल रही है, खोपड़ियाँ और हड्डियाँ इकट्ठा की जा रही हैं। साथ ही डीएनए के नमूने भी लिए जा रहे हैं, ताकि उन्हें दस्तावेजित किया जा सके और आगे विश्लेषण किया जा सके। अमेरिका में मौजूद एक सीरियाई समूह के प्रमुख के मुताबिक दमिश्क के बाहर एक सामूहिक कब्र में असद के पूर्व शासन में मारे गए कम से कम एक लाख लोगों के लाशें हैं। बचाव कर्मियों में शामिल इस्माइल अब्दुल्ला का कहना है कि वे अपने कंधों पर एक भारी बोझ लेकर चल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज हमें संभावित सामूहिक कब्र की सूचना मिलने के बाद, हमने यहाँ जमीन पर सात नागरिकों के अवशेष मिले हैं, अभी

हजारों लोग लापता हैं। सच तक पहुँचने में बहुत समय लगेगा, बहुत ज़्यादा।

इन्-चीफ अहमद अल-शारा ने अल जज़ीरा से कहा कि जिन लोगों ने सीरियाई लोगों के खिलाफ अपराध किए हैं या जिन्होंने अल-असद को उन अपराधों को करने में सक्रिय रूप से मदद की है, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, अबू मोहम्मद अल-जुलानी के नाम से पहचाने जाने वाले अल-शारा ने कहा, 'हम अपने लोगों की उम्मीद के मुताबिक इंसाफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हम अपने लोगों के खिलाफ किए गए अत्याचारों को भूलने नहीं देंगे।' उन्होंने आगे कहा, 'हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र समेत अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से असद सरकार के ज़रिए अपराधों का दस्तावेजीकरण करने में मदद करने की अपील करती है।

भीख देना होगा गुनाह, 1 जनवरी से भीख देने वालों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर

इंदौर प्रशासन ने शहर में भीख मांगने और देने की समस्या पर सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। 1 जनवरी से शहर में भीख देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। यह घोषणा इंदौर कलेक्टर ने की, जिन्होंने इसे एक सामाजिक सुधार का कदम बताया। उन्होंने इंदौरवासियों से अपील की कि वे किसी भी व्यक्ति को भीख न दें, क्योंकि ऐसा करना न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह पाप में भागीदार बनने जैसा है। कलेक्टर ने बताया कि हाल ही में प्रशासन ने शहर में सक्रिय भीख मांगने वाले कई गिरोहों का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह गरीब और जरूरतमंद लोगों का शोषण करते हैं और उन्हें मजबूर करके भीख मांगवाने का काम करते हैं। यह न केवल मानव अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि समाज में असमंजस और अपराध को बढ़ावा देता है। इन गिरोहों का नेटवर्क बेहद संगठित है, जो बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को जबन भीख

मांगवाने के लिए इस्तेमाल करता है। कई मामलों में ये लोग पीड़ितों को उनके घरों से उठाकर या धोखे से फंसाकर इस काम में धकेल देते हैं। कलेक्टर ने इसे गंभीर अपराध बताते हुए कहा कि ऐसे गिरोहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि वे किसी भी परिस्थिति में भीख न दें, ऐसा करने से न केवल अवैध गिरोहों को बढ़ावा मिलता है, बल्कि समाज में गलत संदेश भी जाता है। प्रशासन ने कहा कि जरूरतमंदों की मदद के लिए कई सरकारी और गैर-सरकारी योजनाएँ उपलब्ध हैं, जिनके जरिए सही तरीके से सहायता पहुँचाया जा सकता है। इंदौर प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि शहर में गरीबों में जरूरतमंदों की मदद के लिए कई पुनर्वास और सहायता योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत बेघर और गरीब लोगों को

आश्रय, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएँ मुहैया कराई जाती हैं। प्रशासन ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे जरूरतमंदों की मदद के लिए इन योजनाओं का सहारा लें, न कि भीख देकर।

भीख मांगने और मांगवाने को रोकने के लिए प्रशासन शहर में जागरूकता अभियान भी चला रहा है। इसके तहत पोस्टर, होर्डिंग और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जानकारी दी जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि 1 जनवरी से यह नियम लागू हो जाएगा और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर प्रशासन का यह कदम समाज में व्याप्त एक बड़ी समस्या को खत्म करने की दिशा में है। यह न केवल भीख मांगवाने वाले गिरोहों पर लगाम लगाएगा, बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों को सही मदद और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करेगा।

बीजेपी का नया प्लान, समान नागरिक संहिता संसद से नहीं विधानसभा से होगा लागू

लखनऊ। बीजेपी ने हमेशा से देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने की वकालत की है, और यह मुद्दा जनसंघ के समय से ही पार्टी के एजेंडे का हिस्सा रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तब से इस मुद्दे पर पार्टी ने लगातार जोर दिया है। बीजेपी ने राम मंदिर, अनुच्छेद 370 को हटाने और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों को अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाया था। राम मंदिर का सपना तो साकार हो चुका है, अनुच्छेद 370 को खत्म किया जा चुका है, अब सिर्फ समान नागरिक संहिता को लागू करने का काम बाकी है, जिसे बीजेपी और मोदी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के जरिए अयोध्या में राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ हुआ, और मोदी सरकार ने संसद के जरिए अनुच्छेद 370 को खत्म किया। साथ ही, संसद के जरिए एक देश, एक चुनाव की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं। अब, समान नागरिक संहिता को लागू करने की प्रक्रिया को लेकर बीजेपी ने एक नई रणनीति बनाई है। बीजेपी इस मुद्दे को संसद के बजाय राज्य विधानसभा के माध्यम से आगे बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अपने बयान के माध्यम से संकेत दिए थे। अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान पर चर्चा करते हुए समान नागरिक संहिता के महत्व को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 44 के तहत हमारा संविधान समान नागरिक संहिता की बात करता है, लेकिन यह अभी तक देश में लागू नहीं हो पाया है। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस को दोषी ठहराते हुए कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू किया था, और कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राजनीति शुरू कर दी थी। अमित शाह ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की है, लेकिन कांग्रेस ने हर बार इसे टाल दिया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि उन्नाव खंड में बीजेपी सरकार ने यूसीसी को लागू किया है और इसी मॉडल के तहत बीजेपी शासित अन्य राज्यों में भी यूसीसी को लागू किया जाएगा।

समान नागरिक संहिता का मतलब है कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून हो। इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, संपत्ति के बंटवारे और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर हर नागरिक के लिए समान कानून लागू करना है। वर्तमान में, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम समुदाय के लोग अपने पारिवारिक मामलों का हल करते हैं, लेकिन समान नागरिक संहिता के लागू होने से सभी समुदायों के लिए एक समान कानून होगा।

राम मंदिर बना देने से कोई हिंदुओं का नेता नहीं बन गया: मोहन भागवत



राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने कई मंदिर-मस्जिद विवादों के फिर से उठने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वे ऐसे मुद्दों को उठाकर "हिंदुओं के नेता" बन सकते हैं। भागवत ने साथ ही नये विवादों के उठने पर भी नाराजगी जताई है। हम आपको याद दिला दें कि हाल के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वेक्षण की कई माँगें

अदालतों तक पहुँची हैं, हालाँकि भागवत ने अपने व्याख्यान में किसी का नाम नहीं लिया। भागवत के बयान पर जहाँ हिंदू संतों ने सधी हुई प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि इसे पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भागवत के बयान का स्वागत किया है। हम आपको याद दिला दें कि मोहन भागवत पहले भी कह चुके हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग दूढ़ना सही नहीं है। इस प्रमुख मोहन भागवत ने सहजीवन व्याख्यानमाला में "भारत-विश्वगुरु" विषय पर व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने समावेशी समाज की वकालत की और कहा कि दुनिया को यह दिखाने की जरूरत है कि देश सद्भावना के साथ एक साथ रह सकता है। भारतीय समाज की बहुलता को रेखांकित करते हुए संध प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि रामकृत मिशन ने क्रिसमस मनाया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि "केवल हम ही

ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं।" उन्होंने कहा, "हम लंबे समय से सद्भावना से रहे रहें हैं। अगर हम दुनिया को यह सद्भावना प्रदान करना चाहते हैं, तो हमें इसका एक मॉडल बनाने की जरूरत है। राम मंदिर के निर्माण के बाद, कुछ लोगों को लगता है कि वे नयी जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। यह स्वीकार्य नहीं है।" मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि यह सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। उन्होंने किसी बिना स्थल का उल्लेख किए विना कहा, "हर दिन एक नया मामला (विवाद) उठता जा रहा है। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? यह जारी नहीं रह सकता। भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं।" उन्होंने कहा कि बाहर से आए कुछ समूह अपने साथ कड़वता लेकर आए और वे चाहते हैं कि उनका पुराना शासन वापस आ जाए। उन्होंने कहा,

"लेकिन अब देश संविधान के अनुसार चलता है। इस व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जो सरकार चलाते हैं। आधिपत्य के दिन चले गए।" उन्होंने कहा कि मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन भी इसी तरह की कड़वता के लिए जाना जाता था, हालाँकि उसके वंशज बहादुर शाह जफर ने 1857 में गौहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था।

उन्होंने कहा, "यह तय हुआ था कि अयोध्या में राम मंदिर हिंदुओं को दिया जाना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने दोनों समुदायों के बीच दरार पैदा कर दी। तब से, अलगाववाद की भावना अस्तित्व में आई। परिणामस्वरूप, पाकिस्तान अस्तित्व में आया।" भागवत ने कहा कि अगर सभी खुद को भारतीय मानते हैं तो "चर्चस्व की भाषा" का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख ने कहा, "कौन अल्पसंख्यक है और कौन बहुसंख्यक?"

जिला कार्यालय में धूमधाम से किया गया प्रदेश पदाधिकारियों का भव्य स्वागत



बीपीएस न्यूज

कानपुर। लोक जन शक्ति पार्टी राम विलास के नवनियुक्त प्रदेश सचिव मनोज गुप्ता सोनू तथा प्रदेश उपाध्यक्ष आनन्द सिंह का जिला कार्यालय नौबस्ता में आयोजित स्वागत समारोह जिलाध्यक्ष विपिन यादव के नेतृत्व

में किया गया। सैकड़ों पदाधिकारियों ने प्रदेश सचिव मनोज गुप्ता सोनू तथा प्रदेश उपाध्यक्ष आनन्द सिंह का भव्य स्वागत किया इस मौके पर जिलाध्यक्ष विपिन यादव ने बताया कि अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि समाज के निर्बल निधन असहाय

समाज के उत्थान की दिशा में कार्य करने वाले मनोज गुप्ता जी की कार्यशैली तथा समाज के उत्थान की दिशा में कार्य करने की शैली को देखते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें प्रदेश की जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश सचिव बनाया। जिलाध्यक्ष विपिन यादव के

नेतृत्व में आए पदाधिकारियों ने धरती गूजे आसमान रामविलास पासवान के जोरदार नारे लगाते हुए जोश भरने का कार्य किया। स्वागत कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष ने प्रदेश सचिव मनोज गुप्ता सोनू तथा प्रदेश उपाध्यक्ष आनन्द सिंह को माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। स्वागत कार्यक्रम के पश्चात प्रदेश सचिव मनोज गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में सर्व समाज के उत्थान की दिशा में कार्य किया जायेगा। उन्होंने जिला इकाई का आधार व्यक्त करते हुए कहा कि जल्द ही लोक जन शक्ति पार्टी के द्वारा किए जाने वाला कार्य दिखना शुरू हो जाएगा। इस मौके पर मुख्य रूप से शैलेंद्र सिंह गौर मन्त्रु पंडित ठाकुर अंजली सिंह साधना दीक्षित अमन रावत सतीश चंद्र पांडे अमित दुबे अविरल भाटिया सिमरप्रत सिंह सचिन बाजपेई बृजेश सिंह सेंगर सहित काफी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे।

सीसामऊ नाले के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस फोर्स रही तैनात

- नाले में गिरने से पाँच साल की बच्ची की हुई थी मौत
- क्षेत्रीय विधायक से मेयर ने कहा बुलडोजर तो चलेगा, एक सेकंड की मोहलत नहीं दूंगी

बीपीएस न्यूज

कानपुर। शुक्रवार सुबह सीसामऊ नाले के क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम का प्रवर्तन दस्ता पहुंचा। साथ में भारी संख्या में पुलिस फोर्स थी। नाले के ऊपर बड़ी संख्या में लोगों ने अवैध तरीके से घर बना लिए हैं। कार्रवाई होते देख स्थानीय लोगों ने विधायक नसीम से गुहार लगाई। इस पर मोहलत दिलाने के लिए सपा विधायक नसीम सोलंकी मौके पर पहुंचे थे। मेयर प्रमिला पांडेय ने विधायक की बात सुनने से साफ इनकार कर दिया।

बता दें कि सीसामऊ विधानसभा के अंतर्गत सीसामऊ नाला करीब 20 फीट चौड़ा है। इसको ढकने के लिए बड़ी-बड़ी स्लैब डाली गई है। इसके ऊपर ही लोगों ने अवैध तरीके से स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण कर लिया है ग्वालदोली थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी इलाके में 5 साल की बच्ची मंगलवार को खेलते समय नाले में गिरने से मौत हो गई थी। कुछ लोगों ने बच्ची को निकालने

का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली ग्वालदोली के खलासी लाइन में सीसामऊ नाले के किनारे पितू सिंह परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने बताया कि 2021 में उनके बड़े भाई दिव्यांग लाल बहादुर की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। एक साल पहले उनकी भाभी मिनी अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। इसके बाद वह अपने भाई राजू और राजकुमार के साथ भाई के चार बेटों और चार बेटियों का पालन पोषण कर रहे हैं। मंगलवार को पांच वर्षीय भतीजी रागिनी, सात वर्षीय मानसिक बीमार भतीजे देवा और दो वर्षीय भतीजी आरुषी के साथ घर के सामने स्थित सीसामऊ नाले पर खेल रही थी। तभी एक जगह फर्श टूटी होने के कारण रागिनी नाले में गिर पड़ी। तत्काल पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। करीब दो घंटे बाद घटनास्थल से 500 मीटर दूर सीसामऊ नाले के प्लांट की जाली में बच्ची का शव फंसा मिला। बच्ची की मौत के बाद नगर



निगम ने लोगों को खुद ही अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था। शुक्रवार को महापौर प्रमिला पांडेय नगर निगम के प्रवर्तन दस्ते और पुलिस फोर्स के साथ पहुंचीं। लोगों को घर खाली करने का अनाउंसमेंट किया। आनन-फानन लोगों ने घरों से सामान निकाला और सड़क पर ही रख दिया। इसके करीब 1 घंटे बाद नगर निगम के बुलडोजर ने अवैध निर्माणों को ढहाया। अवैध निर्माण तोड़ने की सूचना पर सपा विधायक नसीम सोलंकी भी मौके पर पहुंचीं।

विधायक नसीम सोलंकी को महापौर ने कहा, बेटा आप यहां से चले जाइए। आपके रहने से माहौल खराब हो सकता है। नसीम सोलंकी ने महापौर से एक हफ्ते का समय मांगा, लेकिन महापौर ने कहा, एक सेकंड का समय नहीं दूंगी। नसीम ने कहा लोगों के छोटे-छोटे बच्चे हैं। महापौर ने कहा कि बच्चा आपका हो या मेरा हो। अगर वो मरता है तो जिम्मेदारी हम सभी की है। अगर मैं किसी का तोड़ दूँ और किसी का छोड़ दूँ तो आप मेरे से आकर शिकायत करना।

फसल अवशेष प्रबंधन पर स्कूल स्तरीय विद्यार्थी जागरूकता कार्यक्रम संपन्न

बीपीएस न्यूज

कानपुर। सीएसए के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्र दिलीप नगर कानपुर द्वारा आज फसल अवशेष परियोजना अंतर्गत स्कूल स्तरीय विद्यार्थी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम श्री बजरंग उच्चतर माध्यमिक कॉलेज भवान कानपुर में आयोजित किया गया। जिसमें 150 से भी अधिक छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया।

यह कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र दिलीप नगर के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर खलील खान के निर्देशन में संपन्न हुआ। जिसमें डॉ खान द्वारा बताया गया कि किसान फसल अवशेषों में आग लगा देते हैं। जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है साथ ही साथ मृदा में पोषक तत्वों का नुकसान होता है। इसीलिए छात्र-छात्राओं को जागरूक करते हुए बताया कि पराली को खेत में मिला देने से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ खलील खान ने बताया कि खेत के अंदर जीवांश की मात्रा कम होने के कारण

सब्जियों, फलों एवं अन्य फसलों में स्वाद व गुणवत्ता की बहुत कमी आ जाती है। जो कि फसल अवशेषों की खाद को मृदा में मिलाने से बढ़ाई जा सकती है। इस अवसर पर केंद्र के वैज्ञानिक डॉ शशिकांत द्वारा बताया गया कि पशुओं द्वारा गोबर की खाद को मिलाने व फसल अवशेषों को मिलाने से मृदा में जीवांश क्षमता बढ़ती है। डॉक्टर कांत ने छात्र

छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि आप अपने माता पिता को फसल अवशेषों में आग लगाने से रोके। शुभम् यादव एवं डॉ गौरव शुक्ला ने भी छात्र छात्राओं को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जागरूक किया। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन पर निर्बंध लेखन, चित्रकला एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया

गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रबंधक श्री नीरज कुमार ने सभी अतिथियों को धन्यवाद दिया। साथ ही छात्र छात्राओं से कहा कि अपने अभिभावकों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जानकारी अवश्य दें। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक जतिन, अवधेश, आदित्य कुमार सहित सहित अन्य विद्यालय स्टाफ एवं कृषि वैज्ञानिक उपस्थित रहे।

मशरूम प्रशिक्षण का समापन, प्रतिभागियों को वितरित किए प्रमाण पत्र

बीपीएस न्यूज

कानपुर। सीएसए के पादप रोग विज्ञान विभाग के मशरूम शोध एवं विकास केंद्र में चल रहे छह दिवसीय (16 दिसम्बर से 21 दिसम्बर 2024 तक) मशरूम प्रशिक्षण का समापन हुआ। इस प्रशिक्षण के समापन अवसर मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ पीके उपाध्याय ने सभी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मशरूम के पोषणीय मूल्य के अलावा मशरूम का उत्पादन एक बहुत ही लाभकारी उद्यम है। उन्होंने प्रशिक्षार्थियों को संबोधित करते हुए बताया कि मशरूम उत्पादन हेतु न्यूनतम भूमि आकार की आवश्यकता होती है। मशरूम जैविक खाद का एक मूल्यवान स्रोत है। जो बागवानी फसल उत्पादन में उपयोग किया जाता है। अधिष्ठाता लखीमपुर खीरी डॉक्टर लोकेंद्र सिंह ने कहा कि मशरूम की खेती विविधता को स्थिरता प्रदान करने और आय बढ़ाने की दृष्टि से लाभकारी है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि मशरूम एक पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक एवं औषधीय गुणों से युक्त रोग रोधक सुपाच्य खाद्य पदार्थ है। उन्होंने कहा कि मशरूम में उपस्थित पोषक तत्व मानव शरीर के निर्माण, पुनः निर्माण एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है।

महिला सशक्तिकरण पर कानपुर में आयोजित हुई महत्वपूर्ण बैठक

बीपीएस न्यूज

कानपुर। सह एसओएचओ जी0 प्रमुख तृप्ति अग्निहोत्री के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें लगभग सात-आठ समूहों के विषयों पर अध्यक्ष और कोषाध्यक्षों के साथ चर्चा हुई। इस बैठक में महिला सशक्तिकरण और रोजगार के अवसरों पर विशेष ध्यान दिया गया।

बैठक में एस एच जी प्रदेश प्रमुख श्रीमती नंदिनी श्रीवास्तव और एस एच जी प्रदेश सह प्रमुख अदिति राय ने महिलाओं के रोजगार हेतु बात की और कैसे इसपर प्रगति हो उसपर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हम एक शहर से दूसरे शहर से जुड़ना चाहते हैं और घर बैठे महिलाओं का व्यापार बढ़ाना चाहते हैं।

जिला महिला प्रमुख सुमन ने बताया कि होली पर महिलाएं नमकीन गुड़िया बनाएं और अपने संघ परिवार में वितरित करें। अरविंद दुबे और दीपेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि हमारा हर तरह का सहयोग है और

हम अपने संघ परिवार के लिए हमेशा तात्पर्य हैं। बैठक के दौरान, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों पर चर्चा हुई और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाना था। मुख्य रूप से प्रदेश महामंत्री अरविंद दुबे, विभाग संयोजक नीरज त्रिपाठी, कानपुर जिला अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह सेंगर, कानपुर जिला महामंत्री चंद्रप्रकाश अग्निहोत्री, एस एच जी प्रदेश प्रमुख श्रीमती नंदिनी श्रीवास्तव, एस एच जी प्रदेश सह प्रमुख अदिति राय, तृप्ति अग्निहोत्री एस एच जी प्रमुख, मीनू चौरसिया एस एच जी सह प्रकोष्ठ प्रमुख, मीनू त्रिवेदी सह महिला प्रमुख, सुमन जिला महिला प्रमुख, माधुरी पांडेय, पुष्पा त्रिवेदी, धर्मेन्द्र शुक्ला, वंदना अग्निहोत्री, पवन कुमार शुक्ल, नवीन, विभाग मीडिया प्रमुख जननायक प्रधान आदि लोग उपस्थित रहे।

सर्दी में जरूरतमंद व्यक्तियों को वितरित किए गए गर्म कम्बल

मूकबधिर एवं दृष्टिबाधित बच्चों के लिए शिक्षा में सोसायटी देती है अनुदान: अध्यक्ष सुनील मेहता

कानपुर। नेककाज चैरिटेबल सोसायटी के द्वारा दादा नगर एसबीआई चौराहे पर भीषण सर्दी को देखते हुए आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद सैकड़ों व्यक्तियों को कम्बल वितरित किए गए। इस मौके पर अध्यक्ष सुनील मेहता एवं उपाध्यक्ष अखिलेश गर्ग ने बताया कि विगत वर्षों से सोसायटी अनाथालय एवं वृद्धाश्रम में खाद्य सामग्री एवं आवश्यक सामग्री वितरित की जाती है। तथा मूकबधिर एवं दृष्टिबाधित बच्चों के लिए शिक्षा में अनुदान दिया जाता है।

वही उपाध्यक्ष अरुण मिश्रा तथा सचिव आलोक त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय त्योहारों पर मजदूरों एवं कामगारों को सोसायटी मिठाईयां तथा अन्य सामग्री वितरित कर उनको खुशियां देने का कार्य सोसायटी करती है। इसी श्रृंखला में आज सैकड़ों जरूरतमंदों को निशुल्क गर्म कम्बल वितरित किए गए। गर्म कम्बल जैसे ही जरूरतमंदों को मिले उनके चेहरे पर मुस्कान दिखी। कम्बल पाकर महिला कामगार गीता ने सोसायटी के सदस्यों की प्रशंसा करते हुए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। अध्यक्ष सुनील मेहता एवं



उपाध्यक्ष अखिलेश गर्ग ने बताया कि वर्ष 2015 से सोसायटी निर्धन तथा निर्बल समाज के उत्थान की दिशा में कार्य कर रही है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डीएमडी कानपुर प्लास्टी पैक लिमिटेड शशांक अग्रवाल के द्वारा किया गया। मुख्य

रूप से श्रीकांत राय आलोक त्रिपाठी एसकेसिंहएसएनसिंहधर्मेन्द्रअवस्थी संजय दास मानता प्रमोद कुमार जेपी शुक्ला केके सिंह शुभांकर बाजपेई यश सनातन राम कुमार यादव बीएल माली सहित काफी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे।

अधिवक्ताओं को आयुष्मान योजना से जुड़वाने का करेंगे प्रयास: सुरेंद्र मैथानी

विधायक मैथानी का अधिवक्ताओं ने किया स्वागत

बीपीएस न्यूज

कानपुर। अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति एवं अधिवक्ता एकता संगठन के सदस्यों ने विधायक सुरेंद्र मैथानी का अंगवस्त्र, पटका और माला पहना कर स्वागत किया।

अधिवक्ताओं ने कहा कि आपने हम अधिवक्ताओं की सुरक्षा जीवन रक्षा और संपत्ति रक्षा तथा अधिवक्ताओं के विरुद्ध लिखी जा रही है फर्जी रिपोर्टों से बचाव हेतु अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को शीघ्र लागू किए जाने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के समक्ष कानपुर के दर्शनपुरवा में



रखी थी। उसी का परिणाम है कि हमारे अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम के लागू किए जाने पर त्वरित कार्रवाई शुरू हुई और संरक्षण अधिनियम के प्रारूप को राज्य विधि आयोग भेज दिया गया। जिसकी सूचना शासन के न्याय

विभाग के विशेष सचिव ने संघर्ष समिति संयोजक पंरवीन्द्र शर्मा पूर्व अध्यक्ष लॉयस एसोसिएशन को पत्र भेज कर दी। हमें विश्वास है कि अब शीघ्र हमारा अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होगा।

सुरेंद्र मैथानी ने पत्र देखकर कहा कि हमारी सरकार अधिवक्ताओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है, अधिनियम का प्रारूप विधि आयोग पहुंच गया है और जो भी औपचारिकताएं होंगी उनको जल्द पूरा करा अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को शीघ्र लागू कराने का प्रयास करूंगा। मैथानी ने यह भी बताया कि अधिवक्ताओं

की चिकित्सा हेतु अधिवक्ताओं को आयुष्मान योजना से जोड़े जाने को मैंने विधानसभा में याचिका लगाई थी सोमवार से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है जिसमें हमारा प्रयास होगा कि अधिवक्ताओं को आयुष्मान योजना से जोड़ दिया जाए। जिसपर अधिवक्ताओं ने पुनः आभार व्यक्त किया।

स्वागत करने वालों में पंडित रवीन्द्र शर्मा, प्रशांत शुक्ला, अतुल सिंह, आशीष गुप्ता, संजीव कपूर, नीरज निषाद, राकेश सिद्धार्थ, प्रणवीर सिंह, दिगम्बर निषाद, रुखसार अहमद, श्रवण निषाद आदि रहे।

रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने किया धरना प्रदर्शन

23 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया

बीपीएस न्यूज

कानपुर। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज दिनांक 19, 12, 2024 को फजलगंज डिपो चुन्नीगंज कानपुर में ट्रेफिक व कार्यशाला के सैकड़ों कर्मचारियों ने प्रेम नारायण शर्मा की अध्यक्षता व अभिषेक कुमार व राजेंद्र प्रसाद पाल के संयुक्त नेतृत्व में 23 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया धरने में बोलेते हुए प्रेम नारायण शर्मा ने बताया कि ड्रगामारी व निजीकरण को रोकने, सविदा व

मृतक आश्रितों को नियमित किए जाने, वेतन विसंगतियों को दूर किए जाने आदि मांगों पर यदि 6 जनवरी 2025 तक परिषद के शीर्ष नेतृत्व से वार्ता कर समाधान नहीं किया गया तो 7 जनवरी 2025 को क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर हजारों कर्मचारियों की संख्या में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से सर्वश्री प्रेम नारायण शर्मा राजेंद्र प्रसाद पाल अभिषेक यादव दिनेश चंद यादव सुनील शर्मा अनंत मनोहर मिश्र विजय यादव कुलदीप राजेश

श्रीवास्तव सुधीर भदोरिया भूपेंद्र सिंह संजय द्विवेदी फहीमुद्दीन

आदि तमाम नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किये।

कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष

आदित्य चौबे को पुलिस ने किया नजर बंद

कानपुर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आवाहन पर उत्तर प्रदेश सरकार के विरोध में दिनांक 18 दिसंबर 2024 को विधानसभा घेराव का आवाहन किया गया था जिसको लेकर कांग्रेस के कई नेताओं को नजर बंद किया गया योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश कांग्रेसियों को जबरन जाने से रोककर विधानसभा घेराव ना करने का भरपूर प्रयास किया गया कानपुर व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष आदित्य चौबे को निवास स्थान पर ही हाउस अरेस्ट किया गया प्रमुख रूप से पूर्व पार्षद प्रत्याशी दिनेश दीक्षित कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सुशील मिश्रा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य विकास सोनकर महामंत्री नीरज त्रिपाठी अंकित शर्मा अलग शंकर शर्मा मोहम्मद आरिफ आदि लोग उपस्थित थे।

अंजनी माता भक्त मंडल द्वारा माता अंजनी का वार्षिकोत्सव हुआ संपन्न



बीपीएस न्यूज

कानपुर। दाल मंडी, बिरहाना रोड, बारातशाला में अंजनी माता भक्त मंडल द्वारा माता अंजनी का वार्षिकोत्सव मनाया गया। अंजनी माता भक्त मंडल द्वारा अंजनी माता का अलौकिक दरबार सजाया गया।

शहर के जाने-माने भजन गायक राजू कुलकर्णी, सुनील स्नेही, यश गुप्ता, देवांश, शीतल, काव्या, महिमा आदि गायकों ने माता के सुंदर भजन गाकर आए हुए भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सोनू शिवांगी गुपु द्वारा झांकी एवं राधे गुपु द्वारा बड़े ही सुंदर

सुंदर संगीत प्रस्तुत किए गए। वहीं प्रिंसी, प्रिंस छोटे बच्चों ने भी कृष्ण राधा भजन पर नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम संयोजक विक्रम अवस्थी ने कार्यक्रम में आए हुए सभी भक्तों का पटक पहनाकर



स्वागत किया। मंडल के सक्रिय सदस्य राजेंद्र अवस्थी, प्रशांत, अरुण अस्थाना सह संपादक बीपीएस न्यूज, दीपक, राजकमल, सतीश, रोहित, विवेक, मनोज, आशुतोष, हिमांशु, विजय,

सुजल आदि लोगों ने भजनों पर नाच गा कर माता को रिझाया कार्यक्रम में पार्षद विकास जायसवाल एवं अन्य विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। जिनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

सुंदरकांड पाठ के बाद कराया गया भंडारा, केक काट मनाया बच्चे का जन्मदिन

बीपीएस न्यूज

कानपुर। नौबस्ता दासु कुंआ स्थित साहू जी महाराज रेस्टोरेंट में सुंदरकांड पाठ का किया गया आयोजन। सुंदरकांड पाठ में हनुमान जी महाराज की सुंदर झांकी ने भक्तों का मन मोह लिया। सुंदरकांड के पाठ में साहू परिवार के साथ क्षेत्रीय लोग व मित्र गण सम्मिलित हुए। सुंदरकांड पाठ के बाद भक्तों को भंडारा भी कराया गया। वहीं साहू जी महाराज रेस्टोरेंट के संचालक सुरेश साहू के पुत्र अर्जुन साहू का आज जन्मदिन भी था। सुंदरकांड में आये सभी भक्तों व मित्रों ने केक काटकर जन्मदिन धूमधाम के साथ



केडीए ने चकेरी में भूखण्ड को सील किया

कानपुर। उपाध्यक्ष महोदय, कानपुर विकास प्राधिकरण, श्री मदन सिंह गर्व्याल के निर्देश के क्रम में आज दिनांक 21.12.2024 को प्रवर्तन जोन-4 क्षेत्र में सम्बन्धित थाना-चकेरी, के अन्तर्गत परिसर सं0-103, 150 फिट रोड, गंगापुर देहली सुजानपुर, कानपुर नगर को सील किये जाने की कार्यवाही की गयी। उक्त कार्यवाही श्री बृजेन्द्र उपाध्याय, विशेष कार्याधिकारी (प्रवर्तन जोन-4) के निर्देशन में श्री सी0के0 चतुर्वेदी, सहायक अभियन्ता, श्री राम दास, अवर अभियन्ता व प्रवर्तन स्टाफ जोन-4, विभागीय सुरक्षा बल व क्षेत्रीय पुलिस बल के सहयोग से सम्पन्न की गयी, उपाध्यक्ष महोदय के निर्देश के क्रम में आगे भविष्य में भी इसी प्रकार की अवैध/अनाधिकृत निर्माणों/विकास के विरुद्ध निर्माणों की सीलिंग/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अभियान चलाकर तेजी से की जायेगी।

डिल्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सदस्यों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में दिया धरना

24 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा

बीपीएस न्यूज

कानपुर। डिल्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के आहवाहन पर डिल्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन कानपुर के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में धरना दिया। धरने को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि फार्मासिस्ट की 24 सूत्रीय मांगों पर सरकार को सकारात्मक निर्णय लेते हुए आदेश जारी करने की आवश्यकता है। धरने में उपस्थित सभी फार्मासिस्टों में रोष व्याप्त है। फार्मासिस्टों को चिकित्सा जगत की रीड की हड्डी कहा जाता है। गांव क्षेत्र में प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं में फार्मासिस्ट की अहम भूमिका होती है। अध्यक्ष दिलीप सिंह सचान ने पदों के मानकीकरण पर जोर देते हुए कहा कि मरीजों को बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सी.एच.सी.



पर चीफ फार्मासिस्ट के 2 पद व फार्मासिस्ट के 3 पद जरूर होने चाहिए। मंत्री विवेक सिंह यादव ने पदनाम परिवर्तन तथा नुस्खा लिखे जाने का अधिकार दिए जाने की मांग पर बल देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अन्य सर्वांग जैसे नेत्र सहायक को नेत्र परीक्षण अधिकारी, स्टाफ नर्स को नर्सिंग अधिकारी का पदनाम दे दिया गया है। उसी प्रकार से फार्मासिस्ट का पदनाम परिवर्तित किए जाने में सरकार को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इससे सरकार पर कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा। धरना दे रहे अन्य फार्मासिस्ट सदस्यों ने सरकार से मांग रखी कि

फार्मासिस्टों की 24 सूत्रीय मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार व्यक्त करते हुए इन मांगों का निराकरण कराया जाये। वहीं मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा गया। धरने में मुख्य रूप से विमल श्रीवास्तव, संजय मिश्रा, अजय सिंह, के.के. त्रिपाठी, कुमुदनी त्रिपाठी, सी.बी. सचान, जे.पी. प्रजापति, नगेंद्र बाजपेई, सपना वर्मा, शैलेंद्र सचान, मुकेश शाक्य, देवेंद्र कुमार, आलोक सोनकर, संजीव साहू, नरेंद्र पांडेय, अविनाश यादव, विनोद कर्नोजिया, अनिल पटेल, दिलीप मिश्रा, राजेश उत्तम, राज कपूर आदि मौजूद रहे।

ईंजन फेल होने से नौ घंटे खड़ी रही मालगाड़ी, वंदेभारत समेत कई ट्रेनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक

शुक्लागंज। गंगाघाट रेलवे स्टेशन के ऋषिनगर बंदरेल केबिन के पास मेन डाउन रेलवे लाइन पर शनिवार की सुबह 9:15 बजे कानपुर से लखनऊ की ओर जा रही एक मालगाड़ी का इंजन फेल हो गया और वहीं खड़ी हो गई। इस बीच लखनऊ की ओर जाने वाली वंदेभारत व शताब्दी एक्सप्रेस समेत कई सुपरफास्ट ट्रेनों को लूप रेल लाइन से धीमी गति से निकाला गया। नौ घंटे बाद लखनऊ से दूसरा



कानपुर। शनिवार को सपाइयों ने गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में कानपुर में बड़ा प्रदर्शन किया। डीएम को ज्ञापन देने से रोके जाने पर सपाइयों ने कलेक्ट्रेट गेट के

बाहर ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कई सपा कार्यकर्ता बंद गेट के ऊपर ही चढ़ गए। वहीं सपाइयों ने अमित शाह की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया।



नवीन मार्केट पार्टी कार्यालय से निकलते ही पुलिस ने सपाइयों को परेड चौराहे पर रोकने की कोशिश की। सपाइयों ने गृह मंत्री अमित शाह की प्रतीकात्मक शवयात्रा निकाली लेकिन पुलिस ने सपाइयों से पुतला छीनने का प्रयास किया।

डॉ भीमराव अम्बेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी व अपमानजनक बयान देने का घोर पाप किया गया है। इसे समाजवादी पार्टी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी।

परेड चौराहे पर काफी देर चली खींचतान के बाद सपाइयों को कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़े। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई। प्रदर्शन के दौरान विधायक अमिताभ बाजपेई, मो. हसन रूमी, जिलाध्यक्ष फजल महमूद, प्रवीण सिंह, बंटी यादव समेत अन्य सपाइयों मौजूद रहे।

विज्ञापन कार्यालय-130/4 - बाबू पुरवा कॉलोनी, किदवई नगर, कानपुर

नवीन गुप्ता
(विज्ञापन प्रतिनिधि)



बीपीएस न्यूज समाचार पत्र व ऑनलाइन न्यूज चैनल (पोर्टल) में विज्ञापन लगवाने के लिए संपर्क करें। मो. 9839625941

बंद पड़े मंदिरों को खोलने की मुहिम शुरू

कानपुर। संभल हिंसा के बाद मुस्लिम बहुल इलाकों में बंद पड़े मंदिरों को खोलने की हुई शुरुआत मेयर प्रमिला पांडे सात थानों की पुलिस फोर्स के साथ मुस्लिम बहुल इलाके बेकनगंज पहुंची 500 मीटर के दायरे में पांच मंदिरों का किया गया निरीक्षण कानपुर हिंसा के आरोपी मुख्तार

बाबा द्वारा कब्जा किए गए राम जानकी मंदिर भी पहुंची मेयर जहां मंदिर गिर चुका है लेकिन कोई कब्जा नहीं मिला मेयर शंकर भगवान के मंदिर पहुंची जहां शिवलिंग के अवशेष थे किंतु शिवलिंग मौजूद नहीं था मंदिर के पिछले हिस्से में लोगों ने कर रखा है कब्जा मेयर ने कब्जा खाली

करने की दी चेतावनी 200 मीटर दूर राधा कृष्ण मंदिर पहुंची जहां पर लोगों ने शटर लगाकर किया है कब्जा मेयर ने जिसका ताला तोड़ने का किया प्रयास तत्काल प्रभाव से कब्जा खाली करने के मेयर ने दिए गए निर्देश कानपुर नगर निगम ने पिछले दिनों कराया था एक सर्वे जिसके मुताबिक

मुस्लिम बहुल इलाकों में 120 से ज्यादा मंदिर बंद पड़े हैं। मंदिरों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा, मूर्तियां कहाँ गई इसकी जांच होनी चाहिए। मेयर के मंदिरों का निरीक्षण के दौरान बजरिया, ग्वालटोली, बेकनगंज, काकादेव, नजीराबाद, कर्नलगंज, चमनगंज थानों का पुलिस फोर्स एक कंपनी पीएसी

NEW SAHU FAMILY RESTAURANT

638y-1, Block Kidwai Nagar
Near - Dasu Kunwa Chauraha Noubasta Kanpur

Owner Management
Suresh Sahu
Mo.-8303637506, 9792526852

Web.site—www.sahufamilyrestaurant.com

Jai Ambey Traders

CARE-TEX
OUR MISSION IS PATIENT CARE

ORDER ONLINE ON amazon

ARUN KUMAR ASTHANA
arunasthana32@gmail.com

7705800400, 9415728160, 9936442547 | 0512-23567401

Head Office: 19/174, Patkapur, Kanpur
Branch Office: 59/88, Shukla Market, Kanpur